वूमेन एक्सप्रेस

www.womenexpress.in

Email: thewomenexpress@gmail.com

• वर्ष 8 • अंक 244 • हिन्दी दैनिक • नई दिल्ली बुधवार 25 नवंबर 2020 • पृष्ठ 8 • मूल्य 1 रूपया • डाक पंजीयन DL (E)-20/5448/2017-19

फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा सबसे पहले कोरोना टीका

कोविड-19: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, किया सतर्क

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली 24 नवम्बर । कोरोना से जंग के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। बैठक के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी, इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते हैं बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को साफ कर दिया कि कोरोना का टीका जब भी आएगा, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। हाल के दिनों में कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति आगाह करते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि कहना पड़े हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साझे प्रयास की बदौलत भारत कोरोना से निपटने में बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है। हमारा रिकवरी रेट बढ़ा है और मृत्युदर कम हुई है। लेकिन इसी के साथ लोगों में लापरवाही भी बढ़ गई है। जबकि मैं बारबार कह रहा हूं कि जब तक दवाई नहीं आ जाती, ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। बैठक के दौरान कोविड19 टीका आपूर्ति, वितरण और टीकाकरण की व्यवस्था के तौरतरीके पर चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए।प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से नीचे और मृत्युदर एक प्रतिशत से नीचे लाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।

जांच और उपचार नेटवर्क के व्यापक विस्तार की चर्चा करते हुए कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाया जाना, घर में आइसोलेट हो रहे लोगों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना, गांवों और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों को सभी सुविधाओं से लैस करना और वायरस से सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाते रहना बेहद जरूरी है। पीएम केयर फंड के उपयोग को लेकर विरोधी दलों की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवालों पर तंज करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्हें राजनीति करने से तो नहीं रोका जा सकता। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फंड का मुख्य जोर ऑक्सीजन मुहैया कराने पर रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं और 160 से ज्यादा नये ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार टीके के विकास के काम पर करीबी नजर रख रही है और वह टीके का विकास और उत्पादन करने वाले भारतीयों के साथसाथ वैश्विक नियामकों, अन्य देशों की सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सम्पर्क में है। उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे नागरिकों के लिए जो टीके आएं, वे अनिवार्य वैज्ञानिक मापदंड पर खरे उतरें। उन्होंने यह भी साफ किया कि वैक्सीन आने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स सभी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम पारदर्शी तरीके से होगा।

टीके के विषय में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं

प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि अभी तक का अनुभव बताता है कि टीके से जुड़ी बहुत सी भ्रामक कथाएं और अफवाहें फैलती है। टीके के दु ष्प्रभावों के बारे में अफवाहें फैलाई जा सकती है। उन्‍ होंने इस बात पर जोर दिया कि टीके के विषय में ज यादा से ज यादा जागरूकता फैलाकर और नागरिक समाज, एनसीसी और एनएसएस के छात्रों तथा मीडिया की मदद लेकर इन अफवाहों से प्रभावी रूप से निपटा जा सकता है।

दिल्ली में बेकाबू हो रहा कोरोना लगातार पांचवे दिन 100 से ज्यादा मौतें

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी दिल्ली में 6,224 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 109 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना की हालत अभी भी सुधर नहीं रहे। मंगलवार को 60 हजार से ज्यादा लोगों की जांच की गई।

वहीं 4943 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोविड19 से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है जबकि 6,224 नए मामले सामने आए हैं। पिछले लगातार दो दिनों से 121 लोगों की मौत हो रही थी। दिल्ली में हालत ये हो गई है कि कब्रिस्तान में शवदाह की जगह नहीं बच रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड19 से निपटने के लिए एक टीम की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संक्रमित मामले के संपर्कों को ढूंढकर उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी है। उन्होंने कहा, 'हमें इस कार्य को गंभीरता के साथ करना है ताकि इस महामारी को रोकने में हम सफल हों।'

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की मौत की घटनाएं बढ़ने के बीच आईटीओ के करीब स्थित दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में अब शवों को दफनाने की जगह कम पड़ रही है, क्योंकि कोविड19 से मरने वाले एनसीआर के अन्य क्षेत्रों के मरीजों को भी यहीं दफनाया जा रहा है। इसका प्रबंधन करने वाले एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

'सूट बूट की सरकार' है चंद पूंजीपतियों की मित्रः राहुल

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए आज फिर कहा कि यह 'सूट बूट की सरकार' है और पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित तरीके से तथा धीरेधीरे काम कर रही है। उसका मकसद सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधने और उनके फायदे के लिए काम करना है। गांधी ने ट्वीट किया, 'सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह क्रोनोलॉजी समझिएः पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया। स्थापित बैंकों में जनता की कमाई सीधे जमा करने की तैयारी जर रही है सूट बूट की सरकार।' जिसमें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विरल आचार्य ने भारतीय कारपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की सिफारिश संबंधी खबर को गलत आइडिया बताया है।

जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक स्कूल नहीं

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बातचीत में किया खुलासा

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच स्कूल खोलने के सवाल पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं।

सिसोदिया ने कहा है कि इस वक्त स्कूल शुरू करना बच्चों को कोरोना की तरफ ढकेलना जैसा होगा। समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में सिसोदिया ने कहा है, दिल्ली में अभी स्कूल खुलने की परिस्थिति नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खोलने का मतलब है कि अपने बहुत सारे बच्चों को कोरोना की तरफ़ ढकेल देना, वो ना आप चाहेंगे ना मैं चाहूंगा, न कोई चाहेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र से हमें सहयोग मिला है, और हमने सहयोग किया भी है आपस में लड़ने से हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने सहयोग मांगा है कि एक हज़ार आइसीयू बेड्स और मिल जाएं कोविड बेड्स हमारे पास साढ़े 8 हज़ार खाली हैं। दिल्ली में बड़ते प्रदूषण

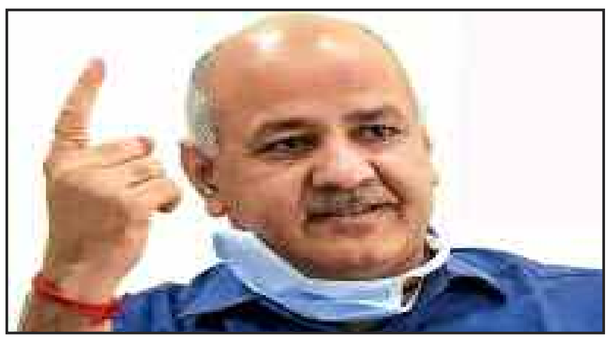

मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बारे में बात करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने पीएम के सामने ये रखा कि कोरोना से हमें एक टीम के रूप में लड़ना चाहिए. हमने केंद्र से पर बात करते हुए सिसोदिया ने कहा, पराली की वजह से कोरोना का कहर बढ़ा. हमें मिलकर एक टीम के रूप में पराली से निपटना होगा। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते केस पर उन्होंने कहा, ÷दिल्ली में केस बढ़े हैं निश्चित रूप से लेकिन डेथ रेट बाकी राज्यों के मुकाबले कम है. अहमदाबाद में डेथ रेट 4.2 है. दिल्ली में डेथ रेट 1.58 के आसपास है. सरकार का मकसद है कि लोगों को बचाया जाए ।

लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, सख्ती भी की जा रही है. मार्केट में अगर भीड़ बढ़ती है तो हम सख़ूती बढ़ाएंगे त्योहार के दौरान भीड़ की उम्मीद थी, अब पुलिस की सख़ूती है कि भीड़ न हो पाए। डिप्टी सीएम ने कहा,सुप्रीम कोर्ट ने जो कोरोना पर कहा है हमें उसे संज्ञान में लेना चाहिए. दिल्ली की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट को हम बताएंगे कि हमने टेस्टिंग बढ़ाई है. हमारे यहां सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई है. हम 60 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट रोज़ कर रहे हैं।

चक्रवात निवार के पहुंचने से पहले चेन्नई में भारी बारिश, आज सार्वजनिक छुट्टी

(विशेष संवाददाता)

चेन्नई । चक्रवात निवार के तमिलनाडु पहुंचने से एक दिन पहले ही चेन्नई सहित राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात निवार को देखते हुए राज्य में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के 25 नवंबर की देर शाम ममल्लापुरम और कराईकल के बीच 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो चेन्नई, कडलोर, पुदुकोट्टई, नागपट्टिनम और विल्लुपुरम सहित तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है। चक्रवात को देखते हुए राज्य में एक दर्जन से अधिक बचाव दल की तैनाती की गई है। जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और तट रक्षक शामिल हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त फणींद्र रेड्डी ने कहा है कि चक्रवात को देखते हुए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि, साल 2018 में गाजा और 2016 में वरदा चक्रवात और भारी बारिश के बाद तमिलनाडु को काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है। रेड्डी ने कहा कि हम यह नहीं चाहते हैं कि राहत शिविर कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर्स बन जाएं।

इसलिए शिविर में कोरोना के लक्षणों के लिए लोगों की जांच की जाएगी। रेड्डी ने कहा कि मंगलवार शाम तक लगभग 1000 लोगों को वहां से दूसरे जगह भेज दिया गया, जब तक चक्रवात तट के पास पहुंचेगा तब तक वहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। चक्रवात को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने बुधवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हुए लोगों से घर में ही रहने का आग्रह किया है।

हालांकि, राज्य में आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा ताकि चक्रवात के कारण आम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि चक्रवात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।

400 रुपये में हो कोरोना टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 24 नवंबर । देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 37 हजार नए मामले आए हैं। बड़ी संख्या में सरकारें टेस्ट भी कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोगों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अलग अलग राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट की अलगअलग कीमत होने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इसपर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की दलील थी अलग अलग राज्यों में इसकी अलगअलग कीमतें हैं। इस टेस्ट की कीमत 400 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वकील अजय अग्रवाल ने सुनवाई में कहा इस टेस्ट की कीमत महज 200 रुपये है इसके बावजूद भी राज्यों में इसकी कीमत बढ़ाचढ़ा कर वसूली जा रही है। जिसका सीधा दबाव जनता पर पड़ रहा। बढ़ी कीमतों के कारण लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

सरकार ने बैन किए 43 मोबाइल चीनी ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं ऐप्स

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली । चीनी ऐप्स बैन किए जाने के बाद अब भारत सरकार ने 43 और ऐप्स को सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक मानते हुए बैन कर दिया है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, ÷भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सरकार द्वारा 43 मोबाइल ऐप अवरुद्ध किए गए हैं.÷बैन किए जाने वाले ऐप्स में कई डेटिंग ऐप्स भी शामिल हैं. इन ऐप्स में अलीबाबा वर्कबेंच, स्नैक वीडियो, कैमकार्ड, टाइनीज सोशल, वीडेट (डेडिंग ऐप), फ्री डेटिंग ऐप, डेट माई एज, ट्रूली चाईनीज, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश प्रमुख है. भारत सरकार ने ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को बैन कर

दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। सरकार के बयान के मुताबिक, इन ऐप के बारे में इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए की गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकर हैं। बयान में आगे लिखा है, इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी।

विधायकों को फोन कर एनडीए तोड़ने की कोशिश कर रहे लालूः सुशील मोदी

(विशेष संवाददाता)

पटना। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि लालू प्रसाद फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे एनडीए विधायकों को मंत्री बनाने तक का ऑफर दे रहे हैं। सुशील मोदी ने खुद फोन कर लालू प्रसाद से बातचीत करने का दावा भी किया। मंगलवार को ट्वीट कर सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने एक मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया है। दावा किया कि वे उस मोबाइल से एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं। विधायकों को फोन करने के पीछे उनकी मंशा एनडीए विधायकों को तोड़ने की है। एनडीए में टूट उत्पन्न करने के लिए वे एनडीए विधायकों को मंत्री बनाने तक का ऑफर दे रहे हैं। सुशील मोदी ने यह

भी दावा किया कि विधायकों को जिस नंबर से फोन आए, उसकी सत्यता जांचने को खुद हमनें (सुशील मोदी) फोन किया। फोन करने पर खुद लालू प्रसाद से बातचीत का दावा करते हुए कहा कि कॉल रिसिव उन्होंने खुद किया। फोन नंबर पर उनसे बातचीत भी हुई। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद से बातचीत में कहा कि वे ऐसी गंदी हरकत नहीं करें। वे जेल में बंद हैं। विधायकों को तोड़ने की कोशिश कहीं से भी उचित नहीं है। लालू प्रसाद को सुशील मोदी ने दो टूक कहा कि एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश में वे कामयाब नहीं होंगे। उनकी मंशा कभी भी सफल नहीं होने वाली है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए होने जा रहे चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुशील मोदी द्वारा लालू प्रसाद पर यह आरोप लगाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से विजय सिन्हा जबकि महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है।

लव जेहाद के खिलाफ अध्यादेश, 10 साल तक की सजा

झूठ बोलकर विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा

(विशेष संवाददाता)

लखनऊ, 24 नवम्बर। लव जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 पास कर दिया। इस नए कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे में अब लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यह अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में ऐसे धर्म

परिवर्तन के लिए वृहत दण्ड का प्रावधान करेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कतिपय सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त करके उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

नए कानून के मुताबिक एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कानून के लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म में परिवर्तन से एक मात्र प्रयोजन के लिए किए गए विवाह पर ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी लाया जा सकेगा। दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपट पूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो यह एक अपराध के रूप माना जाएगा और इस गैर जमानती प्रकृति के अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भुगतनी होगी, साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवयस्क महिला, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में हुआ तो दोषी को 03 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कारावास 03 वर्ष से कम नहीं किन्तु 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि 50,000 रुपए से कम नहीं होगी।

मंगलवार को कैबिनेट से पास इस महत्वपूर्ण अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्राविधान तय किए गए हैं। अध्यादेश के प्राविधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 02 माह पहले सूचना देनी होगी।इसका उल्लंघन करने पर 06 माह से 03 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जबकि इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है।

एक नजर

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के अधिकारियों के विनियमन के लिए जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया गया कि शहर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को दिए गए अधिकारों का विनियमन किया जाए और उन्हें पुलिसकर्मियों के समान वर्दी पहनने से रोका जाए। महिला वकील अमृता धवन द्वारा याचिका में दावा किया गया है कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक दिल्ली महामारी रोग (कोविड19 का प्रबंधन) विनियम 2020 के तहत उन्हें दिए गए 'व्यापक' अधिकारों का 'दुरुपयोग' कर रहे हैं। याचिकाकर्ता अमृता धवन ने वकील अर्पित भार्गव के जरिए दायर अपनी याचिका में दावा किया गया है कि स्वयंसेवकों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में अवगत होने के बावजूद दिल्ली सरकार और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि दिल्ली सरकार और डीडीएमए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि पुरुष स्वयंसेवक नियमों के संदर्भ में महिलाओं की तस्वीरें नहीं लें। याचिका में कहा गया है कि ऐसे उदाहरण भी हैं।

कार्स24 ने जुटाया 20 करोड़ डॉलर का ताजा निवेश

नई दिल्ली। पुरानी कारों की खरीदफरोख्त के ऑनलाइन मंच कार्स24 ने 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,480 करोड़ रुपये) का नया निवेश जुटाया है। कार्स24 ने एक बयान में कहा कि निवेश जुटाने की ईश्रृंखला का नेतृत्व डीएसटी ग्लोबल ने किया। इसमें कंपनी ने 20 करोड़ डॉलर का निवेश हासिल किया। कंपनी में निवेश करने वाले अन्य संगठन एक्सोर सीड्स, मूरे स्ट्रैटेजिक वेंचर्स और अनबाउंड हैं। इस निवेश के लिए कंपनी का बाजार मूल्य एक अरब डॉलर आंका गया। कंपनी इस कोष का इस्तेमाल अपनी नई कारोबार श्रेणियों के विस्तार, उत्पाद नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के लिए करेगी। कंपनी सिकोइया इंडिया, किंग्सवे कैपिटल और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इत्यादि से अब तक कुल 40 करोड़ डॉलर का निवेश हासिल कर चुकी है। कंपनीके सहसंस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी विक्रम चोपड़ा ने कहा कि इस निवेश के साथ हम अपने उत्पाद को नवोन्मेषी बनाना और हमारी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेंगे।

लौह अयस्क की गोलियों के अवैध निर्यात पर तत्काल पूर्ण पाबंदी लगाए सरकार

नई दिल्ली। खनन कंपनियों के संगठन एफआईएमआई ने केंद्र सरकार से लौह अयस्क की गोलियों (पेलेट्स) के अवैध निर्यात पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि इससे घरेलू इस्पात कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) ने इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। एफआईएमआई ने सरकार से एकीकृत इस्पात उत्पादक कंपनियों के इस्पात बिक्री के लिए कीमत निगरानी और विनियमन व्यवस्था बनाने में भी तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की कीमतें बढ़ने का किसी तरह का अकारण असर घरेलू इस्पात की कीमतों पर न पड़े। एफआईएमआई ने कहा, '' हमारा सरकार से अनुरोध है कि केआईओसीएल के अलावा अन्य निजी इकाइयों द्वारा लौह अयस्क की गोलियों के अवैध निर्यात पर तत्काल पूर्ण पाबंदी लगायी जाए। इससे घरेलू इस्पात विनिर्माता कंपनियों की कच्चे माल की जरूरत पूरा करने में मदद मिलेगी।''

रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा

भारतीय रेलवे, शहरी विकास और दिल्ली सरकार मिलकर निकालेंगे समाधान

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली 24 नवंबर। भारतीय रेलवे की जमीन पर दिल्ली में वर्षों से बसी 48 हजार झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। फिलहाल इन झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।

भारतीय रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 4 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने उच्चतम न्यायलय को सूचित किया कि फिलहाल दिल्ली में रेलवे लाइनों के साथ 48 हजार झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रेलवे, शहरी विकास और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर समाधान निकालेंगे और तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।

बता दें कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गीझोंपडि़यों को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी

झोंपडि़यों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह आदेश एम सी मेहता मामले में पारित किया था।

भारतीय रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्लीएनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण हैं जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ यह बहुत ज़्यादा है, जो कि करीब 48000 झुग्गियां है।

रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था जिसके तहत इन झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था लेकिन राजनैतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है।

> **समाधान निकलने तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा**

भारतीय रेलवे ने कहा कि इसमें काफी अतिक्रमण तो रेलवे के सुरक्षा जोन में है जो कि बेहद चिंताजनक है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि तीन महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनैतिक दबाव और दख़लंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजन और विरल आचार्य ने कहा कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की सिफारिश चौंकाने वाली

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली, 24 नवंबर। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चैंकाने वाली है। दोनों का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में कारोबारी घरानों की संलिप्तता के बारे में अभी आजमायी गयी सीमाओं पर टिके रहना अधिक महत्वपूर्ण है।

रिजर्व बैंक के द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) ने पिछले सप्ताह कई सुझाव दिये थे। इन सुझावों में यह सिफारिश भी शामिल है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक शुरू करने का लाइसेंस दिया जा सकता है। राजन और आचार्य ने एक साझा आलेख में यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को अभी छोड़ देना बेहतर है।

आलेख में कहा गया है, 'जुड़ी हुई बैंकिंग का इतिहास बेहद त्रासद रहा है। जब बैंक का मालिक कर्जदार ही होगा, तो ऐसे में बैंक अच्छा ऋण कैसे दे पायेगा? जब एक स्वतंत्र व प्रतिबद्ध नियामक के पास दुनिया भर की सूचनाएं होती हैं, तब भी उसके लिये खराब कर्ज वितरण पर रोक लगाने के लिये हर कहीं नजर रख पाना मुश्किल होता है।'' इस कार्य समूह का गठन देश के निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व से संबंधित दिशानिर्देशों और कंपनी संचालन संरचना की समीक्षा करने के लिये किया गया था।

आलेख में कार्य समूह के इसी प्रस्ताव की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि बड़े पैमाने पर तकनीकी नियामकीय प्रावधानों को तार्किक बनाये जाने के बीच यह (कार्पोट घरानों को बैंक का लाइसेंस देने संबंधी सिफारिश) सबसे महत्वपूर्ण सुझाव 'चैंकाने वाला है।' आलेख में कहा गया, ''इसमें प्रस्ताव किया गया है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की मंजूरी दी जाये। भले ही यह प्रस्ताव कई शर्तों के साथ है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है: ऐसा अभी क्यों?'' यह आलेख रघुराम राजन के लिंक्डइन प्रोफाइल पर सोमवार को पोस्ट किया गया।

डालर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली। स्थानीय शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से पूजीं का प्रवाह लगातार बने रहने और कोरोना वायरस के टीके की दिशा में प्रगति के समाचारों के बीच मंगलवार को अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 10 पैसे की तेजी के साथ 74.01 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हई। बाजार सूत्रों ने कहा कि कोविड19 के टीके के जल्द आने की बढती उम्मीदों के बीच निवेशकों में जोखिम उठाने की ललक बढ़ी है। जिसके कारण रुपये में लगातार तीसरे सत्र में लाभ दर्ज हुआ। इसके अलावा, घरेलू शेयर बाजार में मजबूती, विदेशी निधियों के सतत निवेश और डॉलर के कमजोर होने से भी रुपये को समर्थन मिला। अन्तरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 74.10 पर खुला। कारोबार के दौरान रुपये की विनिमय दर 73.88 के उच्च स्तर और 74.12 के निम्न स्तर तक गयी। भाव के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ प्रति डालर 74.01 पर बंद हुआ।

डाक विभाग के कंधों पर होगी कोरोना वैक्सीन को देश के हर हिस्से में पहुंचाने की जिम्मेदारी

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। भले ही कोरोना वैक्सीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई हो, लेकिन इसको पूरे देश में पहुंचाने के नेटवर्क पर काम शुरू हो गया है। 'हिन्दुस्तान' को मिली जानकारी के मुताबिक डाक विभाग ने मास वैक्सीनेशन के लिहाज से अपने नेटवर्क की मैपिंग शुरू कर दी है और सरकार के निर्देश मिलते ही युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन आने के बाद इसे देश के कोनेकोने में पहुंचाने के लिए पोस्टल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, विभाग ने इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोल्डचेन बनाने की तैयारी पर भी बातचीत शुरू कर दी है। ताकि वैक्सीन आने के बाद उसे जरूरी तापमान पर देश के सुदूर इलाकों तक पहुंचाया जा सके। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक, अभी वैक्सीन किस रूप में आएगी और कितने तापमान पर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस बारे में पुख्ता निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन पहले से तैयारी इसलिए शुरू हो गई है ताकि निर्देश मिलने के बाद

बिना समय गंवाए इस पर काम किया जा सके। इस काम में विभाग की डेढ़ हजार से ज्यादा गाड़ियां, जिनमें करीब एक हजार जीपीएस से लैस गाड़ियों को इस काम में लगाए जाने की उम्मीद है। विभाग में इस संभावना पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निश्चित तापमान को बनाए रखते हुए बॉक्स मुहैया कराए जा सकें, जिन्हें निश्चित समय में डाक विभाग के कर्मचारी तय जगह पर पहुंचा पाएंगे। डाक विभाग पहले भी टीबी से जुड़े सैम्पल को नियत तापमान पर रिकॉर्ड समय में टेस्टिंग लैब्स में पहुंचाने का काम कर चुका है। साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन यानि नाको के साथ जरूरी दवाओं और सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन से विभाग जुड़ा रहा है। नाको की तरफ से भी विभाग को तापमान सही रखे जा सकने वाले बॉक्स में जरूरी दवाइयां और सैंपल दिए जाते थे, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था। कोरोना महामारी के दौरान जब देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था उस दौरान डाककर्मियों ने बड़े पैमाने पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानि पीपीई किट को भी जिला अस्पतालों और निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाने का काम किया है।

मी टू मामला: अकबर, रमानी ने मानहानि के मामले में समझौते से इनकार किया

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वेबवार्ता)। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और पत्रकार प्रिया रमानी ने आपराधिक मानहानि के मामले में कोई भी समझौता करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अकबर ने रमानी के खिलाफ यह मामला दायर कर रखा है।

अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि यदि रमानी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगती हैं तो वह अपने मुवक्किल से मामले को बंद करने के लिए कहेंगी। वहीं, रमानी की ओर से पेश वकील भावुक चैहान ने कहा कि हालांकि उनकी मुवक्किल अपने बयान पर कायम है और यदि अकबर शिकायत वापस लेना चाहते हैं तो वह भी ऐसा कर सकते हैं। अदालत ने मंगलवार को पूछा कि क्या दोनों पक्षों के वकीलों के पास बातचीत की कोई गुंजाइश है या दरवाजे बंद हैं? रमानी के वकील ने 'न' में जवाब दिया और कहा, ''नहीं, हमारा रुख स्पष्ट है। रमानी अपने बयान पर कायम हैं। यदि शिकायतकर्ता शिकायत वापस लेना चाहता है तो वह इसे संज्ञान में ला सकते हैं।'' दूसरी ओर, लूथरा ने कहा, ''मैंने अपने मामले को देखा है। यदि आरोपी माफी मांगती है...यदि उनकी की तरफ से कोई संकेत है तो मैं अपने 'ब्रीफिंग वकील' से कहूंगी।'' ब्रीफिंग वकील मुवक्किल और वरिष्ठ अधिवक्ता के बीच की कड़ी होते हैं। रमानी के वकील के अभिवेदन के बाद अकबर की वकील ने कहा, ''हमें गुणदोष पर जारी रखना चाहिए।'' पत्रकार ने अकबर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले उनके साथ यौन कदाचार किया था। अकबर ने इसपर रमानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की।

पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा: गोपाल राय

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली, 24 नवंबर। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर प्रदूषण को लेकर पंजाबहरियाणा की सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पंजाबहरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। राय ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने पराली के लिए बायो डिकम्पोजर तकनीक लागू की, उसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने के लिए हमने एयर क्वालिटी कमीशन के सामने पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। राय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर बनाए गए कमीशन के सामने सरकार ने पेटीशन लगाई है। संबंधित राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को कमीशन निर्देश दे

कि वो भी दिल्ली सरकार की तरह पूसा इंस्टिट्यूट द्वारा निर्मित बायो डिकम्पोजर का पराली गलाने के लिए उपयोग करें। उन्होंने कहा कि 15 सदस्यीय प्रभाव आकलन समिति ने राजधानी में पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिहाज से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा विकसित बायोडिकम्पोजर के घोल की प्रभावशीलता का पता लगाया है तथा इस संबंध में जानकारी सोमवार को पर्यावरण मंत्रालय के 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और नजदीक के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भेजी गई है। पर्यावरण मंत्री राय ने बताया कि आयोग को सूचित किया गया है कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल राजधानी दिल्ली में 2,000 एकड़ भूमि पर किया गया तथा इसने फसलों के 9095 अवशेष (पराली) को 1520 दिन के भीतर खाद में बदल दिया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं के कारण बीते 15 दिन से कोविड19 के मामले बढ़े हैं।

एआईएफएफ उच्चतम न्यायालय की शरण में कार्यकारी समिति के कार्यकाल में विस्तार की मांग

नई दिल्ली, 24 नवंबर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी मौजूदा कार्यकारी समिति को उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बरकरार रखने का आग्रह किया है क्योंकि न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक चुनाव कराने के लिए अब तक नया संविधान तैयार नहीं कर पाए हैं। प्रफुल्ल पटेल की अगुआई वाली मौजूदा कार्यकारी समिति का चार साल का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है और एआईएफएफ ने घोषणा की है कि उसकी वार्षिक आम बैठक 21 दिसंबर को होगी। सामान्य हालात में चुनाव वार्षिक आम बैठक के दौरान होते। ऐसी स्थिति में पटेल खेल संहिता के तहत दोबारा चुनौती पेश करने के पात्र नहीं होते क्योंकि वह 2012 से एआईएफएफ अध्यक्ष हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में आदेश जारी करके एसवाई करैशी और भास्कर गांगुली की मौजूदगी वाली प्रशासकों की समिति का गठन किया था जिससे कि खेल संहिता के अनुसार एआईएफएफ का संविधान तैयार किया जा सके। नया संविधान हालांकि अब तक तैयार नहीं हुआ है और इसलिए एआईएफएफ उच्चतम न्यायालय की शरण में गया है। एआईएफएफ महासचिव कुशाल दास द्वारा सभी मान्यता प्राप्त इकाइयों को लिखे पत्र के अनुसार, ''माननीय उच्चतम न्यायालय के 10 नवंबर 2017 के ओदश के अनुसार संविधान तैयार नहीं होने के कारण एआईएफएफ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है जबकि 21 दिसंबर 2020 में कार्यकारी समिति का चार साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए महासंघ ने 21 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।''

केंद्र के अस्पतालों में 1000 आइसीयू बेड सुरक्षित कर दिए जाएं

अरविंद केजरीवाल ने की पीएम से अपील, दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी

(लोकेश निरवाल)

नई दिल्ली, 24 नवंबर,। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक के दौरान दिल्ली में कोविड19 के ताजा हालात और इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तार से जानकारी दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी कोविड के समान्य बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन आईसीयू बेड की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने पीएम से दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1000 आइसीयू बेड दिल्ली के मरीजों के लिए सुरक्षित करने की अपील की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर 8600 पॉजिटिव केस के साथ 10 नवबंर को अपने शिखर पर थी, लेकिन अब पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है। कोरोना की तीसरी लहर को अधिक खतरनाक बनाने में पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली के प्रदूषण का विशेष योगदान रहा है। हम चाहते है कि आपके (पीएम) नेतृत्व में दिल्ली के पड़ोसी मुख्यमंत्री पराली को खत्म करने के लिए एक टीम की तरह काम करें। देश भर में

बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वर्तमान हालातों के बारें में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी देते हुए कोविड से लड़ने के लिए किए गए काम की जानकारी दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड के लिए आरक्षित कुल बेड में से 9400 बेड भरे हुए हैं, जबकि अभी 8500 बेड खाली हैं। अभी कोरोना के समान्य बेड को लेकर हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। अभी हमारे पास कोरोना के समान्य बेड की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। दिल्ली में कुल आईसीयू बेड में से करीब 3500 आईसीयू बेड भरे हुए हैं और अभी 724 आईसीयू बेड खाली हैं। सीएम ने कहा कि आईसीयू बेड बढ़ाने में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार के सफदरजंग और एम्स जैसे अस्पतालों में कुछ दिनों के लिए 1000 बेड दिल्ली वासियों के लिए सुरक्षित कर दिए जाएं, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और पूरी महामारी के दौरान हमें और दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार से जो मदद मिली है, उसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को आगे बताया कि दिल्ली में कोरोना की पहली लहर जून के महीने में आई थी, उस दौरान दिल्ली में 20 हजार सैंपलों की जांच प्रतिदिन की गई थी। दिल्ली सरकार ने सितंबर में जांच का दायरा बढ़ाते हुए 60 हजार प्रतिदिन कर दी थी। दिल्ली में अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। दिल्ली ने 8600 पॉजिटिव केस के साथ 10 नवबंर को तीसरी लहर का शिखर देखा था। 10 नवबंर के बाद से दिल्ली में पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है, लेकिन बढ़ती मृत्युदर चिंता का विषय है और हमें मृत्युदर को कम करना होगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी दर के साथ मृत्युदर भी लगातार कम होती जाएगी।

महिला हेल्पलाईन न.

डीएमआरसी—155370
सीआईएसएफ—22185555
दिल्ली पुलिस—1091
दिल्ली सरकार—181
कहीं भी—कभी भी—1090

समाचार एजेंसी
वेब वार्ता
पल-पल की ख़बर हर पल
समाचार एजेंसी का सदस्य बनने के लिए संपर्क करें
9650061234

तीन दिनों तक हरियाणा-दिल्ली सीमा रहेगी बाधित, रहें सावधान

रास्ता क्लीयर होने पर ही घर से निकलें, बीच में फंस सकते हैं

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली 24 नवंबर अगले तीन दिनों के बीच में अगर आप दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते हैं या फिर हरियाणा से दिल्ली आना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं। कृषि बिलों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों सेदिल्ली घेरने आ रहे किसानों के चलते हरियाणादिल्ली का संपर्क बिगड़ सकता है। लिहाजा, आप रास्ता क्लीयर होने पर ही घर से निकलें।

हालांकि, इसको लेकर हरियाणा सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज विशेष ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि 25 नवंबर व 26 नवंबर को सड़क द्वारा पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले स्थानों तथा 26 नवंबर व 27 नवंबर को हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले स्थानों पर यातायातअवरोधों का सामना करना पड़ सकता है।

विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर व 27 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो' का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनजर राज्य में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

इन प्रबंधों का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने व सार्वजनिक शांति बनाए रखने, यातायात व सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के कामकाज को सुविधाजनक

सुनिश्चित करना है। सरकार ने कहा है कि कोविड19 महामारी की स्थिति के कारण लागू होने वाले निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है।

सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक दिल्ली जाने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों द्वारा विभिन्न बॉर्डर प्वाइंटस से होते हुए पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने की संभावना है। इसके अलावा, हरियाणा से दिल्ली जाने वाले प्रदर्शनकारियों का मुख्य फोकस चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला से दिल्ली, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से दिल्ली और पलवल से दिल्ली होंगे। अंबाला जिला के शंभू बॉर्डर, भिवानी जिला के गांव मुढ़ाल चौक, करनाल जिला की घरौंडा अनाज मंडी, झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर तथा सोनीपत जिला के राई राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में भी प्रदर्शनकारियों द्वारा एकत्रित होने का एक विशेष आह्वान किया गया है।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक उचित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह भी संभव है कि पुलिस द्वारा पंचकूला, अंबाला, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सड़कों के माध्यम से पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले बॉर्डर प्वाइंटस पर 25, 26 और 27 नवंबर को यातायात को मोड़ा जा सकता है या सड़क को अवरुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार, दिल्ली की ओर जाने वाले चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, यानी अंबाला से दिल्ली, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से दिल्ली और पलवल से दिल्ली की तरफ भी अंबाला जिला के शंभू बॉर्डर, भिवानी जिला के गांव मुढ़ाल चौक, करनाल जिला की घरौंडा अनाज मंडी, झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर तथा सोनीपत जिला के राई राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से यातायात को मोड़ा जा सकता है या सडक़ को अवरुद्ध किया जा सकता है।

एक नजर

जेएसडब्ल्यू स्टील ने एमएसएमई की मदद के लिए वेबसाइट शुरू की

नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू स्टील ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपकमों (एमएसएमई) पर केंद्रित वेबसाइट शुरू की है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस वेबसाइट के जरिये एमएसएमई कम मात्रा में भी इस्पात की खरीद कर सकेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशकवाणिज्यिक विपणन एवं कॉरपोरेट रणनीति जयंत आचार्य ने कहा कि सामान्य रूप से एमएसएमई छोटी कंपनियां होती हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करती हैं। उचित मूल्य और समय पर आपूर्ति से उन्हें प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। आचार्य ने कहा कि इसी मकसद से जेएसडब्ल्यू स्टील ने एमएसएमई के लिए यह वेबसाइट शुरू की है। ''हम एमएसएमई को इस पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे हम उनकी जरूरतों को समझ सकेंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी अपने इस्पात उत्पादों पर तरजीही मूल्य के जरिये एमएसएमई की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। इसे 202425 तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। देश में छह करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं।

यमुना खादर इलाके में लोगों ने खुले में जलाए तार आप नेता बुलाई पुलिस

नई दिल्ली । एक तरफ सरकार वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें कर रही है. वहीं कुछ लोग रात में यमुना खादर जाकर तारों का बंडल जलाकर प्रदूषण कर रहे थे. मौके पर पहुंचे आप नेता ने न केवल आग बुझवाई और इसकी जानकारी स्थानीय एसडीएम और पुलिस को दी. पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी आपना सामान मौके पर छोड़कर फरार हो गया. यह मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के दूसरा पुश्ता उस्मानपुर के ठीक सामने यमुना खादर का है. आम आदमी पार्टी के सीलमपुर विधानसभा के नेता अनिल जैन ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि रात होते ही खादर के जंगलों के बीच से धुआं उठते देखा जा रहा था. आप नेता इसी सूचना के आधार पर दूसरे पुश्ते के ठीक सामने स्थित खादर के जंगल में पहुंचे तो आग की ऊंची ऊंची लपटें देखीं. जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कुछ लोग तारों के बड़े बड़े बंडलों पर कुछ डालकर जला रहे थे. तारों के गुच्छे तो ऊंची लपटों के साथ जल रहे थे, जबकि कुछ सामान वहीं पास में रखा हुआ था. अनिल जैन ने पहले तो इन लोगों को वहां तार जलाने से रोका और जल रहे आग के बंडलों पर पानी डालकर आग बुझाई. उन्होंने तत्काल ही घटना की जानकारी स्थानीय एसडीएम और एसएचओ शास्त्री पार्क को दी. भेजने के लिए कहा. सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही तार जलाकर प्रदूषण फैलाने वाले आरोपी वहां से निकल कर फरार हो गए।

दिल्ली के विकासपुरी में 70 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूनकर हत्या

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान विकासपुरी निवासी अत्तम सिंह के तौर पर की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को शाम करीब पांच बजकर बीस मिनट पर पुलिस को सूचना मिली कि विकासपुरी में मकान संख्या एच358 के निकट गोली चलने की घटना हुई है। लहूलुहान हालत में अत्तम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। गोली उनके सिर में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग अत्तम सिंह के घर के आसपास देखे गए थे।

आयुर्वेदा शिक्षा के संशोधन नियमों की अधिसूचना को वापस लिया जाएः IMA

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली 24 नवम्बर । सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) द्वारा उल्लंघन और अतिक्रमण के स्तर से राष्ट्र के सभी आधुनिक चिकत्सा पेशेवर विश्वासघात महसूस कर रहे हैं। आईएमए पोस्टग्रेजुएट आयुर्वेदा शिक्षा के संशोधन नियमों से संबंधित अधिसूचना को वापस लेने की मांग करता है। अधिसूचना में एमएस शल्य तंत्र (सामान्य सर्जरी) नाम के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। शल्य तंत्र और शालक्य तंत्र के अंतर्गत आधुनिक चिकित्सा सर्जिकल प्रक्रियाओं की एक लंबी लिस्ट को शामिल किया गया है। ये योग्यताएं आधुनिक चिकित्सा के दायरे, अधिकारियों और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमएस (सामान्य सर्जरी) नाम के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए योग्य माना है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. राजन शर्मा ने बताया कि, आयूष मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि तकनीकी शर्तें सीसीआईएम संशोधनों को अलग दृष्टिकोण के साथ नहीं देखा जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चिकित्सा बहुलतावाद और पार्श्व प्रविष्टि मिश्रण की नींव रखने

और आधुनिक विकास मानव जाति की सामान्य विरासत हैं। आईएमए इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार करता है, क्योंकि यह चिकित्सा प्रणालियों को मिलाने का एक भ्रामक छलावरण है। यह चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार के मिश्रण पर एक कठोर प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। की बात करती है। नीति आयोग ने चिकित्सा शिक्षा, अभ्यास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसंधान में चार समितियों का गठन किया है, जिससे सभी प्रणालियों को चिकित्सा के एक एकीकृत प्रणाली में आधिकारिक रूप से मिलिया जा सके।

दिल्ली के किसानों ने खोली केजरीवाल सरकार के झूठ की पोलः आदेश गुप्ता

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली, 24 नवंबर । दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार के झूठ के खिलाफ पोल खोल अभियान के तहत मंगलवार को नरेला विधानसभा के घोघा गांव, बवाना विधानसभा के दरियापुर, हरेवली, नागल, बाजीपुर और माजरा डबास के कृषि क्षेत्रों का दौरा कर रियलिटी चेक किया और किसानों की व्यथा सुनी।

इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कहा कि करोड़ों खर्च करके केजरीवाल सरकार यह प्रचार कर रही है कि वह दिल्ली के किसानों को पराली से खाद बनाने की दवा बांट रही है, जिससे खाद बन रही है जो असल में एक फरेब मात्र है, किसानों को ऐसी कोई दवा केजरीवाल सरकार की ओर से मिली ही नहीं जिससे खाद बनती हो। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा, प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार सहित किसान मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान किसानों ने दिल्ली भाजपा

अध्यक्ष आदेश गुप्ता के सामने अपना दुखड़ा रोया और केजरीवाल सरकार की पर्ची दिखाते हुए बताया कि केजरीवाल सरकार की मंडी में उनसे 8001000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा गया। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार पंजाब में जाकर दावा कर रही है कि वह किसानों को 2600 प्रति क्विंटल दे रही है। उन्होंने पूछा कि क्या केजरीवाल सरकार की नैतिकता खत्म हो चुकी है जो वह राजनीति के लिए अन्नदाता को धोखा दे रही है? उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अन्य राज्यों में प्रचार के लिए बड़ेबड़े होर्डिंग लगाएं कि वह दिल्ली के किसानों को पराली से खाद बनाई जा रही हैं जिससे प्रदूषण मे कमी आ रही है जबकि दिल्ली के किसानों के खेतों में अभी तक एक ग्राम खाद भी नहीं बनी है, यदि कहीं बनी है तो बताएं। दूसरी ओर आज भी दिल्ली के खेतों में पराली के अम्बार लगे हुए है और केजरीवाल सरकार की ओर से कोई मदद ना मिलने के कारण किसानों को गेहूं की बुआई में देरी हो रही है। किसानों की समस्या बस यही नहीं है बल्कि केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा ही नहीं दिया है, उन्हें कृषि उपकरणों की खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, देश भर में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के किसानों को मिलती है, उन्हें ट्यूबवेल लगाने की अनुमति तक नहीं है, जमीन की दाखिल खारिज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों पर मुकदमे किए जा रहे हैं और उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर में केजरीवाल सरकार किसानों की हितैषी बनने का ढोंग करने के लिए किसानों को केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा देने का प्रचार कर रही है ।

छात्रों को आर्थिक मदद से लेकर संसाधन तक मुहैया करा रहे हैं छात्र व कॉलेज

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वेबवार्ता)। देश भर में कोविड19 से उपजी स्थिति का सीधा असर उनकी आय पर पड़ा है। डीयू के विभिन्न कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में छात्र ऐसे वर्ग से आते हैं, जिनके पास समुचित संसाधन नहीं हैं। किसी के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो किसी के पास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उपकरण या डेटा पैक के पैसे नहीं हैं। लेकिन डीयू के सेंट स्टीफंस सहित अन्य कॉलेजों के विद्यार्थी डीयू के ऐसे छात्रों की मदद के लिए आगे आए हैं। यह कॉलेजों से मदद न लेकर पूर्व छात्र, अपने सहयोग या अन्य माध्यमों से मदद ले रहे हैं। कुछ कॉलेज भी इस दिशा में अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्राएं, राजधानी कॉलेज की युवा सोसाइटी तथा कुछ कॉलेजों के शिक्षक भी अपने स्तर पर छात्रों की मदद के लिए आगे आए हैं। सेंट स्टीफंस कॉलेज में बीए प्रोग्राम अंतिम वर्ष की गोवा निवासी छात्रा ईविता ने छात्रछात्राओं की समस्या को देखते हुए एक पोस्टर ट्विट किया और लिखा कि डीयू के छात्रों के लिए आपकी आर्थिक मदद चाहिए। उन्होंने इसके नीचे नंबर भी लिखा। बाद में गूगल फार्म भी जारी किया गया जिससे जरूरतमंद छात्र उसे भरकर इन छात्रों को भेज सकें।

ईविता बताती हैं कि 100 से अधिक छात्रों ने अब तक फीस के लिए आवेदन किया था जिसकी मदद की गई। 10 नवंबर को ट्विट करने के बाद कई लोग आगे आए। उन लोगों से लगभग 6 लाख रुपये एकत्रित हुए। ईविता बताती हैं कि सेंट स्टीफंस के छात्र छात्राओं की एक टीम है जो गूगल फार्म पर आए आवेदन की स्क्रीनिंग करती है। हम छात्रों से उनकी बैंक डिटेल के साथ उनकी समस्या, जरूरत के साथ आय प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड भी मांगते हैं।

फसलों के विविधीकरण की दिशा में पंजाब के किसानों ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाएः तोमर

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली, 24 नवंबर । केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि खेतीकिसानी के क्षेत्र में पंजाबहरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें गर्व है कि इन राज्यों के किसानों की अथक मेहनत के कारण भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि सरप्लस है।

उन्होंने कहा कि पंजाब गेहूं व धान में अग्रणी रहा है लेकिन अब भूजल स्तर कम होने से फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए पंजाब के किसानों ने सफलतापूर्वक कदम आगे बढ़ाए हैं। तोमर ने मंगलवार को पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में सुखजीत मेगा फूड पार्क का विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, वहीं सम्बद्ध क्षेत्रों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि उपजों की एमएसपी को बढ़ाया गया है, 10 हजार नए एफपीओ बनाने की स्कीम सरकार लाई, किसानों को ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, छोटे किसानों जिनकी संख्या 86 प्रतिशत है, उन्हें लाभ पहुंचाने पर पूरा ध्यान है। किसानों को एफपीओ के माध्यम से अनेक फायदे होंगे। एफपीओ भारत सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से स्वीकृतियां देना प्रारंभ हो चुका है, पंजाब को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 10 हजार करोड़ का फंड बनाया गया है, जिससे किसानों को वाजिब लाभ मिल सकेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अभी तक 37 मेगा फूड पार्कों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिनमें से 20 पूर्व में प्रारंभ हो चुके हैं।

शिक्षाविद रश्मि शर्मा को यूरोप से मिली डॉक्टरेट की उपाधि

नई दिल्ली 24 नवम्बर । प्रसिद्ध समाजसेविका, शिक्षविद एवं किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल नई दिल्ली की प्रिंसिपल रश्मि शर्मा को यूरोप की संस्था ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से संम्मानित किया है। अंतरराष्टीय एम्बेसडर रश्मि शर्मा को यूरोप की संस्था यूरोपीय रोमन अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर बजराम हालिटी ने बोर्ड की स्वीकृति से मानवता और मानव अधिकारों में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया है। उल्लेखनीय है कि रश्मि शर्मा को मानव अधिकारों व सामाजिक सरोकारों के लिए राष्टीय व अंतरराष्टीय स्तर पर अनेक अवार्डो से नवाजा गया है। आप कई राष्टीय व अंतरराष्टीय संस्थाओं की एम्बेसडर भी है। पूर्व में श्रीलंका की संस्था द्वारा भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। रश्मि शर्मा गत 13 वर्ष से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं मुख्यतः बच्चों की शिक्षा,नारी उत्थान एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान रहता है। पर्यावरण

के क्षेत्र में इन्होंने बच्चों को और उनके अभिभावकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना,कोरोना काल मे बच्चों को ऑन लाइन शिक्षा व अभिभावकों को कोरोना से बचाव के तरीके बताकर जागृत करने का सराहनीय कार्य किया है।

मेट्रो के 20 साल आयु वर्ग वाले आधे से अधिक लोगों को जीवनकाल में हो सकता है मधुमेह

नई दिल्ली, 24 नवंबर (वेबवार्ता)। देश में 20 साल आयु वर्ग के लोगों में से आधे से अधिक पुरूष एवं दो तिहाई महिलाओं को उनके जीवनकाल में मधुमेह की बीमारी हो सकती है और उनमें से अधिकतर लोगों में टाइप टू का मधुमेह होने की आशंका है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। इस अध्ययन में भारतीय महानगरों में रह रहे किसी भी आयु वर्ग या 'बॉडी मास इंडेक्स' के लोगों में उनके जीवनकाल में मधुमेह होने की आशंका का आकलन किया गया है। इस अनुसंधान को 'डायेबेटोलॉजिया' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि देश में करीब 7.7 करोड़ वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं और इस वजह से देश पर पहले ही स्वास्थ्य बोझ है। 2045 तक इस संख्या के दुगुना होने की आशंका है । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2045 तक देश में 13.4 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हो सकते हैं । उन्होंने बताया कि देश में शहरीकरण तेजी से हो रहा है और गुणवत्ता पूर्ण आहार का अभाव तथा शारीरिक गतिविधि में कमी का भी इस छिपे महामारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है । इस अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं ने देश के शहरी हिस्से में उम्र, लिंग एवं बीएमआई आधारित मधुमेह की दर का आकलन किया है। यह सेंटर फॉर कार्डियोमेटाबोलिक रिस्क रिडक्शन इन साउथ एशिया के आंकड़ों (20102018) पर आधारित है । उन्होंने 2014 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गई समयसारणी से आयु, लिंग, और शहरीमृत्यु दर का तथा मधुमेह के प्रसार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शोध इंडिया डायबीटिज (20082015) का विश्लेषण किया । विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि 20 साल के ऐसे पुरूष एवं महिलायें जिन्हें आज मधुमेह नहीं है, उनमें जीवन काल में यह बीमारी होने का खतरा क्रमशः 56 एवं 65 प्रतिशत है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि पूरे जीवन काल में आम तौर पर महिलाओं के मधुमेह से पीड़ित होने का खतरा अधिक रहता है। अध्ययन के अनुसार ऐसे लोग जिनकी उम्र अभी 60 साल है और जिन्हें मधुमेह नहीं है उनमें से करीब 38 फीसदी महिलाओं एवं 28 प्रतिशत पुरूषों में यह बीमारी होने का खतरा रहेगा। इसमें चेताया गया है कि इन अनुमानों पर मोटापे का पर्याप्त असर है और मेट्रोपोलिटन शहरों में रहने वाले मोटे लोगों के जीवनकाल में, जिनकी उम्र 20 साल है ।

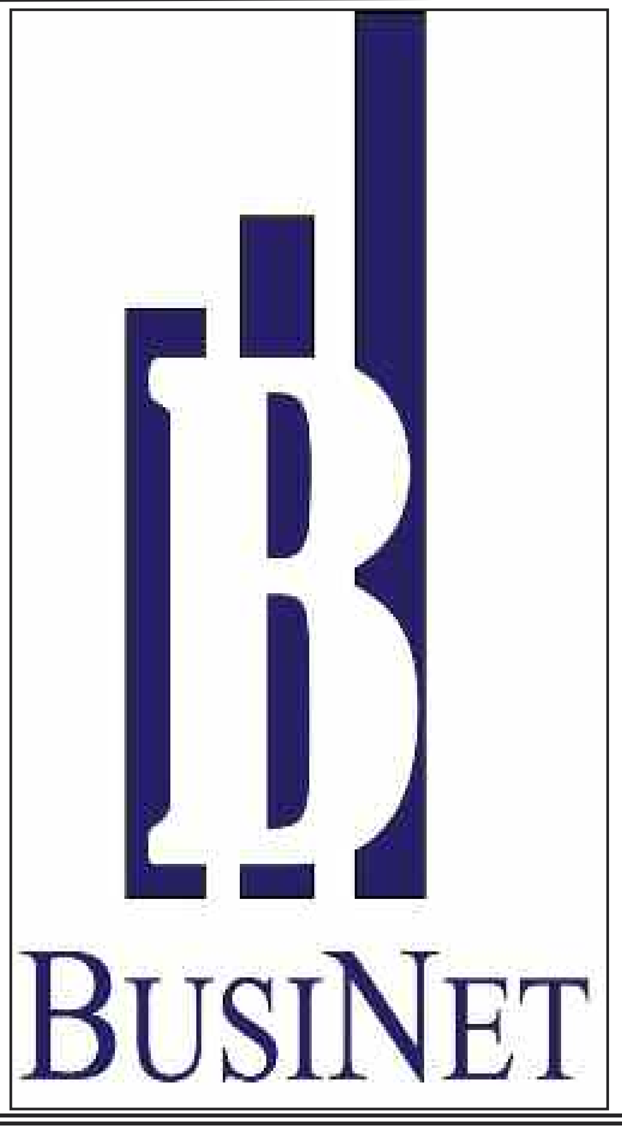

संपादकीय

सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण हो

रिजर्व बैंक के पास अधिकार हैं कि वह निजी बैंकों को आदेश दे सकता है कि वे किन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलकर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। दुर्भाग्यवश इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को इस प्रकार के दिशानिर्देश देने के स्थान पर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जो हितकर होने के स्थान पर अहितकर साबित हुआ। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, लेकिन इस कदम का देश को भारी मूल्य अदा करना पड़ रहा है। प्रति वर्ष बजट में हजारों करोड़ रुपए जनता से टैक्स वसूलकर इन सार्वजनिक बैंकों को जीवित रखने के लिए घाटा पूर्ति के लिए दिए जा रहे हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं तो अवश्य उपलब्ध कराई गई हैं, परंतु सरकारी बैंक के घाटे की भरपाई के लिए गरीब जनता पर टैक्स आरोपित किया जा रहा है पिछले तीस महीनों में असफल होने वाले प्राइवेट बैंकों में यस बैंक और पीएमसी बैंक के बाद तीसरे नंबर पर लक्ष्मी विलास बैंक है। इस बैंक के संकट में आने के साथ ही सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों ने मांग की है कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किसी सार्वजनिक बैंक के साथ किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि प्राइवेट बैंकों में धांधलेबाजी होती है और जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन सार्वजनिक और प्राइवेट बैंकों के बीच एक मौलिक अंतर है। सार्वजनिक बैंकों के सभी शेयर भारत सरकार के पास होते हैं। इनके शीर्ष अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर का बैंक पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसे में बैंक अधिकारी के लिए संभव है कि उसकी निगाह बैंक के लाभ पर न होकर अपनी कमाई पर हो। जैसे यदि किसी सार्वजनिक बैंक के मुख्य अधिकारी ने किसी डूबती हुई कंपनी को भारी ऋण दिया और उसमें एक रकम घूस के रूप में प्राप्त कर ली तो मुख्य अधिकारी को लाभ होगा, लेकिन बैंक को घाटा होगा। इतना सही है कि यदि देश का वित्त मंत्री सजग हो तो घाटे में जाने वाले मुख्य अधिकारियों पर कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि यह सख्ती केवल उन्हें पदच्युत करने अथवा स्थानांतरित करने तक सीमित हो जाती है।

मुख्याधिकारी के लिए यह संभव है कि एक बैंक में घाटा लगाने के बाद वह दूसरे पद पर पुनः लाभ कमाए। मूल बात है कि सार्वजनिक बैंक के मुख्य अधिकारी और मालिक (सरकार) के स्वार्थ अलगअलग होते हैं। तुलना में प्राइवेट बैंकों में मुख्याधिकारी और मालिक के बीच में गहरा समन्वय होता है। जैसे किसी प्राइवेट बैंक के मुख्याधिकारी द्वारा घटिया लोन दिए गए और बैंक को घाटा लगा तो बैंक के मालिक को भी घाटा लगेगा, जबकि सार्वजनिक बैंक में ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंक को घाटा लगने के साथ उस बैंक के शेयर की कीमत गिरेगी और मालिक की साख भी तदनुसार कम होगी। इसलिए मूल रूप से प्राइवेट बैंक के मुख्याधिकारी का प्रयास रहता है कि वह बैंक को लगातार अच्छी दिशा में ले चले ताकि उसकी स्वयं की नौकरी और उसके मालिक दोनों के हित सधते रहें। इसके बावजूद सभी बैंकों द्वारा घटिया लोन दे दिए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा कफे काफी डे, नीरव मोदी और जेट ऐयरवे जैसी कंपनियों को ऋण दिए गए जो कि आज खटाई में पड़ गए हैं। यह कह पाना कठिन है कि ये ऋण गलतफहमी में या फिर भली प्रकार सोचविचार के दिए गए या फिर इसमें गड़बड़ी की गई। बहरहाल यह सही है कि ऐसे ऋण देने से प्राइवेट बैंक को घाटा लगता है और वह घाटा शीघ्र ही बाजार और समाज के सामने आ जाता है और बैंक की साख प्रभावित होती है। तुलना में यदि सरकारी बैंकों के द्वारा भी इसी प्रकार के घटिया लोन दिए गए तो उनका पर्दाफाश नहीं हो पाता है। बैंकों को घाटा लगता रहता है और सरकार द्वारा उनके घाटे की भरपाई करने के लिए इनमें उत्तरोत्तर अधिक पूंजी का निवेश करती रहती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों में बीस हजार करोड़ रुपए की रकम पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया है।

महिला हेल्पाइन

डीएमआरसी	155370
सीआईएसएफ	22185555
दिल्ली पुलिस	1091
दिल्ली सरकार	181
कहीं भी कभी भी	1090

हिंदी दैनिक वूमेन एक्सप्रेस

खबर एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें
चेम्बर नंबर-302, वधवा बिजनेस सेंटर, डी-288-89/10,
नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टैशन गेट नंबर -1,
विकास मार्ग, नई दिल्ली - 110092
मोबाइल : 07042999974/ 09013518518
प्रधान संपादक : खुशबू पाण्डेय
प्रबंध संपादक : विनोद मिश्रा
राजनीतिक संपादक : नीता बुधौलिया
विज्ञापन प्रबंधक : रिजवाना नसीम
कानूनी सलाहकार : लखमी चन्द
www.womenexpress.in
Email : thewomenexpress@gmail.com

इंदौर कार्यालय

102 , राजानी भवन , हाई कोर्ट के सामने,एम् ,जी रोड , इंदौर (मध्यप्रदेश)
रजनी खेतान (ब्यूरो चीफ)
मोबाइल : 08770587699, 09826024018

प्रयागराज कार्यालय

17/33, महात्मा गांधी मार्ग
(माया बाजार) सिविल लाइन्स।
फोन : 05322560285
09415215390
प्रबंध संपादक : विनोद मिश्रा

खोखले साबित हो रहे हैं महिला सुरक्षा के तमाम दावे

महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिये हर साल 25 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बेहद डरावनी स्थिति से रूबरू होना पड़ेगा। आँकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल 15 19 आयु सीमा की लगभग डेढ़ करोड़ किशोर लडकियाँ अपने जीवन में कभीनकभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। तीन अरब महिलाएँ वैवाहिक बलात्कार की शिकार होती हैं। हिंसा की शिकार 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की हत्या उनके परिजनों द्वारा ही की जाती है। प्रतिदिन 3 में से एक महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। भारत को संस्कार, संस्कृति और मर्यादा की त्रिवेणी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में नारी अस्मिता को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है यस्य पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। मगर आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। न नारी की पूजा हो रही है और देवताओं की जगह सर्वत्र राक्षस ही राक्षस दिखाई दे रहे है। समाज के नजरिए में भी महिलाओं के प्रति अब तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसा लगता है जैसे हमारा देश भारत धीरेधीरे बलात्कार की महामारी से पीड़ित होता जा रहा है। यौन अपराध चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पिछले चार दशकों में अन्य अपराधों की तुलना में रेप की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और दोषियों को सजा देने के मामले में हम सबसे पीछे हैं। दो साल की बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक दुष्कर्म की शिकार हो रही है। ऐसे में कानून के पालनहार कोई सख्त कदम उठाने के बजाय अपनी गलतियों को छिपाने के लिए नित नए बहाने ढूंढ रहे है।

आजकल रोज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की खबर दिखाई जाती रहती है परंतु इसकी

रोकथाम के उपाय पर चर्चा कहीं नहीं होती है। इस तरह के अत्याचार कब रुकेंगें। क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बन खुद की बारी का इंतजार करेंगे। लड़कियों पर अत्याचार पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं अगर इसके रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं किये गये। आज भी हमारे समाज में बलात्कारी सीना ताने खुले आम घूमता है और बेकसूर पीड़ित लड़की को बुरी और अपमानित नजरों से देखा जाता है । न तो समाज अपनी जिम्मेदारी का माकूल निर्वहन कर रहा है और न ही सरकार। ऐसे में बालिका कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेगी यह हम सब के लिए बेहद चिंता की बात है। भारत में महिलाओं को देवी के सामान पूजने की परंपरा है। इसी देश में आज महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन छेड़छाड़, हत्या और बलात्कार जैसी आमानवीय घटनाएं होती रहती है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं अब छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नही है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल औरतों के साथ होने वाली हिंसा में 7.3 फीसदी का इजाफा हुआ है। महिलाओं के साथ हिंसा की वारदातों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2018 में महिलाओं के खिलाफ हुए 3,78,236 अपराधों के मुकाबले 2019 में 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए। वर्ष 2019 में प्रतिदिन 87 प्रकरण बलात्कार के दर्ज हुए। यानि आलोच्य अवधि में भारत में बलात्कार के कुल 31,755 मामले दर्ज किए गए । सबसे ज्यादा 5,997 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए । उत्तर प्रदेश में 3,065 मामले और मध्य प्रदेश में 2,485 मामले दर्ज किए गए। सच तो यह है कि एक छोटे से गांव से देश की राजधानी तक महिला सुरक्षित नहीं है। अंधेरा होते होते महिला प्रगति और विकास की बातें छूमंतर हो जाती हैं। रात में विचरण करना बेहद डरावना लगता है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुँचने की चिंता सताने लगती है। देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी नहीं आरही है। भारत में आए दिन महिलाएं हिंसा और अत्याचारों का शिकार हो रही हैं। घर से लेकर सड़क तक कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। देश में महिला सुरक्षा को लेकर किये जा रहे तमाम दावे खोखले साबित हुए है। महिला सुरक्षा को लेकर देशभर से रोजाना अलगअलग खबरें सामने आती रहती हैं। देश में महिलाओं की स्थिति पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावों और वादों के बाद भी उनकी हालत जस की तस है। महिलाएं रोज ही दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और अत्याचार से रूबरू होती है।

बाल मुकुन्द ओझा
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार
मालवीय नगर, जयपुर ।

www.womenexpress.in

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के लिए कौन जिम्मेदार?

कब तक सहेगी महिलाएं इस समाज में जुर्म ? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं ? आज की यह मॉडर्न पीढ़ी अपनी सोच नहीं बदलती। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं इस सदी में महफूज नहीं है । आए दिन महिलाओं पर होने वाले अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है इसमें सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के हैं.। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और कई बड़े शहरों में रह रही महिलाओं में असुरक्षा की भावना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया में महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा की खबरें छाई रहती है। वर्तमान में भारत में नारी शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है। नारियां, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, उद्यमी आदि अनेक क्षेत्र में कार्यरत है। राजनीतिक और समाज सेवा में भी नारी की पर्याप्त सहभागिता है तथा अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों को रोजगार में सरंक्षण मिल रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी वर्तमान में नारियां असुरक्षित है। उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है तथा दुराचारी लोगों के आचरण से नारियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। समाज में कुछ असभ्य लोग नारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

उनके साथ जोर जबस्ती करते हैं सरेआम नारियों के पर्स छीनना,गले की चेन झपटना, युवतियों से छेड़छाड़ करना, गलत नियत से जान पहचान कर उनका यौन शोषण करना आदि अनेक कुकृत्य अब आम बात हो गई है। हर रोज महिलाओं को थप्पड़ ओ लातों पिटाई अपमान धमकियों यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है यहां तक कि उनके जीवन साथी या उनके परिवार के सदस्य उनके त्याग कर देते हैं प्रताड़ित महिलाएं इनके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती है। अनेक डॉक्टर्स,नर्स,स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं कई लोग नेता और समाज के बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए। अकेले नहीं जाना चाहिए और जल्दी घर आ जाना चाहिए। इन्हीं कारणों से उनके साथ दुष्कर्म होता है।

मैं पूछती हूं कि क्या लड़कियों को इन सब की आजादी नहीं है ? लड़कियों के साथ दुष्कर्म होना उनकी दैनिक दिनचर्या नहीं बल्कि हमारी छोटी सोच इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं बल्कि लिंगानुपात का घटना भी महिलाओं के लिए किसी अपराध से कम नहीं है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख शहरों में राज्य में लिंगानुपात बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम और आप यही कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति हो जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस समस्या से निपटने में कारगर सिद्ध हो सकती है और हम सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए। हम और आप महिलाओं के बिना किसी समाज की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं।

वहीं समाज का एक मूलभूत अंग होती है तो हम यह सब क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें इस तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। महिलाओं पर होने वाली दुष्कर्म जैसे अपराध को रोकने के लिए अपनी और समाज की सोच को बदलना होगा और इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए वास्तव में महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को सक्षम होना होगा भीरूता को स्त्री का गहना मानना स्वयं स्त्री को तजना होगा। हिम्मत,वीरता और साहस को उसे अपने महत्वपूर्ण गुण बनाना होगा जो डरता है उसे दुनिया डराती है। सामाजिक स्तर पर सोच में बदलाव भी लाया जा सकता है यह लंबी प्रक्रिया होगी जिसमें आधी सदी भी लग सकती है जिस दिन से माताऐंअपने बेटे और बेटियों की परवरिश में अंतर करना छोड़ देगी उस दिन से सामाजिक स्तर पर सोच में बदलाव कर बीच पड़ जाएगा। वर्तमान में जघन्य अपराध से समाज को मुक्त करने तथा नारियों में असुरक्षा का भाव दूर करने की आवश्यकता है और जनता के सहयोग से नारी समाज को उत्पीड़न से बचाया जा सकता है।

ऐसे में यह लगता है कि इन अपराधों को रोकने का एक ही उपाय है कि हमें महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा और उन्हें समाज में बराबर का हक मिलना चाहिए। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि जहां नारियों की इज्जत होती है, वहां भगवान का वास होता है। फिर भी यहां पर महिलाओं पर अन्य किसी देश की तुलना में ज्यादा अपराध होता है। समाज के कुछ मनचले ही दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को समाज द्वारा ही सजा देनी चाहिए क्योंकि कानून से बचने के सारे उपायों को यह जानते हैं और कानून का उनको कोई डर भी नहीं होता है।

सुनीता मूंढ
बाड़मेर, राजस्थान।

www.womenexpress.in

अहंकारी व बेलगाम सत्ता के नियंत्रण के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी

हमारा देश वर्तमान समय में अव्यवस्था, अराजकता तथा व्याकुलता के दौर से गुज़र रहा है। पहले से ही बेरोज़गारी व मंहगाई जैसे अभूतपूर्व हालात का सामना कर रहे देश के नागरिकों के सामने कृषक आंदोलन तथा उत्तर प्रदेश में महिलाओं विशेषकर दलित महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार व जघन्य अपराधों ने इन असामान्य हालात में जलती आग में घी डालने का काम कर दिया है। केवल एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश के हाथरस, आज़मगढ़,बलरामपुर तथा भदोही व बाराबंकी में बलात्कार व नृशंस हत्या जैसी कई घटनाओं ने उन सत्ताधीशों की शासन क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया है जिन्होंने दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुँचने के लिए जनता में यही भय फैलाया था कि यू पी ए के शासन में क़ानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट है,बेटियों का बलात्कार हो रहा है और वे पूरी तरह असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज को गुंडा राज बताया जाता था। और अपना शासन आने पर जनता को राम राज का एहसास दिलाने का सपना दिखाया गया था। परन्तु देश की जनता के लिए राम राज का सपना तो मात्र एक दुःस्वप्न साबित हो चुका है। देश की जिन बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ % का नारा दिया गया था और इस मिशन की मार्केटिंग में सैकड़ों करोड़ रूपये फूँक दिए गए थे उन्हीं बच्चियों के साथ केवल बलात्कार ही नहीं हो रहा बल्कि शासन के अधिकारियों द्वारा भी जिस तरीक़े का क्रूरता पूर्ण बर्ताव किया जा रहा है उसका दूसरा उदाहरण स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिला। हाथरस की घटना जिसने देश में उबाल पैदा कर दिया है,इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहाँ दलित युवती का कथित तौर पर पहले सामूहिक बलात्कार किया गया फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गयी व ज़ुबान काट डाली गयी। उसके बाद इन साक्ष्यों को मिटाने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा मरणोपरांत उस मृतक बच्ची को उसके मां बाप की अनुमति के बिना,बिना किसी संस्कार संबंधी धार्मिक रीति रिवाज को पूरा किये हुए, यहाँ तक कि रात में अंतिम संस्कार हरगिज़ न किये जाने जैसी हिन्दू

मान्यताओं व परंपराओं के विरुद्ध भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मध्यरात्रि में उस बदनसीब का दाह संस्कार स्वयं पुलिस वालों के हाथों मिट्टी का तेल व पेट्रोल आदि चिता में छिड़ककर कर दिया गया। इसी तरह बलरामपुर व बाराबंकी की घटनाओं में भी पुलिस पर पीड़ित मृतक युवती का संस्कार देर रात उसके परिजनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कराए जाने का आरोप है। उम्मीद तो यही थी कि दलितों के नाम पर व दलित वोटों के सहारे राजशाही ठाठ बाठ हासिल करने वाली मायावती,राम विलास पासवान तथा राम दास अठावले जैसे नेता हाथरस व अन्य स्थानों पर दलित बेटी के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तथा पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर अपनी हमदर्दी का इज़हार करेंगे। परन्तु दलित रहनुमाओं ने चुप्पी साध ली। हाँ मायावती ने ट्वीटबाज़ी बयानबाज़ी कर अपना फ़र्ज़ अदा करने का दिखावा ज़रूर कर दिया। ऐसे में निश्चित रूप से न केवल हाथरस के पीड़ित दलित परिवार के साथ बल्कि देश के समस्त वंचित,पीड़ित व उपेक्षित समाज के साथ विपक्षी पार्टियों के खड़े होने की ज़रुरत थी।और इस फ़र्ज़ को बखूबी निभाने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा निभाया गया व निभाया जा रहा है। सत्ता से सवाल पूछने की सज़ा के रूप में कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी को पुलिसिया धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा यहाँ तक की उनके चोट लगने व घायल होने का भी समाचार आया। इसी प्रकार हाथरस जा रहे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पर पुलिस ने कथित रूप से लाठी चार्ज किया जिसमें टी एम सी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और प्रतिमा मंडल धक्का मुक्की के दौरान नीचे गिर गये।उधर लखनऊ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया। बड़े ही आश्चर्यजनक तरीक़े से हाथरस में पीड़िता के गांव की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे तथा राजनैतिक दलों के लोगों व मीडिया कर्मियों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सरकार के इस तानाशाही रवैये को न केवल भाजपा नेता उमा भारती ने ग़लत बताया बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कई पूर्व महानिदेशकों व आई पी एस अधिकारियों ने भी इसकी निंदा की व इस तरह की पुलिस कारगुज़ारी को ग़लत व ग़ैर ज़रूरी भी बताया। बहरहाल इस समय विपक्ष आए दिन ख़राब होते जा रहे इस तरह के वातावरण को लेकर राम राज का वादा व दावा करने वाले सत्ताधीशों से दो दो हाथ कर रहा है। परन्तु दलाल मीडिया और सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति नज़र आ रही है। महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर रहने वाली स्मृति ईरानी भी कांग्रेस की सक्रियता को राजनीति करना बता रही हैं। यदि ऐसी घटनाओं पर विपक्ष ख़ामोश रहे तो यही मीडिया कहता नज़र आएगा कि इतने बड़े हादसे के बाद विपक्ष ख़ामोश क्यों है? क्या सांप सूंघ गया है? क्या विपक्ष मुर्दा गया है? क्या विपक्ष शक्तिहीन हो गया है? क्या विपक्ष समाप्त हो गया है ?आदि आदि। और जब यही राहुल व प्रियंका गाँधी तथा उनकी पार्टी के हज़ारों नेता व कार्यकर्ता मज़लूमों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनके इस कर्तव्य को राजनीति करना बताया जा रहा है ? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जनता का मिज़ाज भांपते हुए हाथरस के पुलिस अधीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक सहित दो पुलिस निरीक्षकों को बर्ख़ास्त तो ज़रूर कर दिया।

तनवीर जाफ़री

www.womenexpress.in

स्त्री हिंसा रोकने का दिवस नहीं लैंगिक समानता जरूरी

राफेल ट्रूजिलो को लैटिन अमेरिका के इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक माना जाता जिसकी तानाशाही के खिलाफ तीन बहनों पैट्रिया मर्सिडीज मिराबैल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबैल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबैल ने आवाज़ बुलंद की जिसकी परिणाम वही हुआ जो अपेक्षित था कि उस क्रूर शासक ने 25 नवंबर, 1960 को एक निर्मम आदेश देकर उनकी हत्या करवा दी जिनकी स्मृति में महिला अधिकारों के समर्थक व कार्यकर्ता इस दिन को वर्ष 1981 से इन तीनों बहनों की मृत्यु की वार्षिकी के रूप में मनाते एवं 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस तरह वह दिन जब तीन स्त्रियों को तानाशाही के विरुद्ध परचम लहराने के लिये मौत के घाट उतार दिया गया वह सम्पूर्ण विश्व में अन्य महिलाओं के ऊपर की जाने वाली हिंसा को रोकने का महत्वपूर्ण दिवस बन गया मगर, उसके बावजूद भी ज्यादा कुछ बदलाव नजर आता नहीं क्योंकि, औरतों पर अत्याचार का सिलसिला सदियों से बदस्तूर जारी है ।

ये नहीं कि केवल निचले तबके या अशिक्षित लोगों में इस तरह की समस्या अधिकतर देखी जाती हो बल्कि, उच्च शिक्षित एवं हाई सोसाइटी की महिलाएँ भी अपने घरों ही नहीं कार्यस्थल पर भी शारीरिक व मानसिक हिंसा का शिकार होती वो भी तब जब तमाम तरह के कानून, संवैधानिक अधिकार व संगठन स्त्रियों को समर्थन देने पूरी दुनिया में विद्यमान मगर, ये जहां हो या वो जहां वो उसे दोयम दर्जे पर ही रखा जाता और उस पर शासन करने की प्रवृति का ये आलम कि उसके लिए हर तरह की तिकड़म आजमा ली जाती क्योंकि, हर किसी को ये इल्म कि नारियों के पास बाहुबल भले कम हो लेकिन, आत्मबल व इच्छाशक्ति इतनी जबरदस्त होती कि हृदयाघात या दिल की बीमारियों से मरने वालों में पुरुष मरीजों की संख्या अधिक पाई जाती कि स्त्री हर हाल में मिटकर, टूटकर भी फिर खड़ी हो जाती बस, उसका आत्मसम्मान शेष रहे अतः ज्यादातर मामलों में इस पर ही हमला करने की कोशिश की जाती पर, आदमियों में ये जज्बा कम ही देखने मिलता कि उन्हें बिना संघर्ष किये सब हासिल होता तो वे उतने मजबूत नहीं बन पाते जितनी स्त्रियां जो पैदाइश से लेकर अंतिम सांस तक जीने के लिये लड़ती अपने हुक़ूक़ छीनकर लेती है ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सही यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर ही महिला हिंसा की बात करें तो एनसीआरबी यानि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2007-2016 के बीच महिला अपराध संबंधी जारी आंकड़े के मुताबिक, भारत में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामले 83 प्रतिशत बढ़े हैं व शील भंग करने के प्रयास का मामला 119 प्रतिशत बढ़ गया और बलात्कार के मामलों की संख्या भी 83 प्रतिशत बढ़ी है इसके अलावा पारिवारिक हिंसा और उत्पीड़न के मामले भी 45 प्रतिशत बढ़े हैं ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति किस हद तक खराब हो चुकी है वो भी तब जबकि, जन जागरूकता व शिक्षा के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है ऐसे में इस तरह के दिवस की सार्थकता व औचित्य तभी सिद्ध होंगे जब स्त्रीपुरुष के बीच भेदभाव व असमानता की लकीर मिटाकर उन्हें केवल मानव समझा जायेगा और खुद को एकदूसरे से सर्वश्रेष्ठ मानने का भाव दोनों के बीच शेष न रहेगा अन्यथा इस स्थिति में अधिक बदलाव की संभावना बेमानी है ।

सुश्री इंदु सिंह
स्वतंत्र लेखिका व चिंतक
नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)।

www.womenexpress.in

प्रशासन बेईमान, सरकार अनजान, किसान परेशान

यह तो शत प्रतिशत सत्य है कि धान की खेती का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धान की खेती से मीथेन गैस तीव्र गति से उत्सर्जित होता है। फिर तो माननीय उच्च न्यायालय को पूरी धान की कृषि को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मगर धान की पराली जलाने को प्रतिबंधित कर और कृषकों जागरूक करने की योजना का आदेश देकर माननीय उच्च न्यायालय व सरकार को यह लग रहा है कि आदेश का पालन प्रशासन साफसुथरा कर रहा है। परन्तु यहाँ स्थिति तो कुछ और ही है, जागरूकता के नाम पर किसानों को डरानेधमकाने के साथ साथ नगदी वसूली भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से जारी है। उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों में इस बात को लेकर सरकार के प्रति भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और नाराजगी हो भी क्यों नहीं? सरकार ने आदेश देकर किनारा कर लिया, परन्तु किसान के साथ कैसा वर्ताव प्रशासन कर रहा है? इसकी भी तो जानकारी सरकार को लगानी चाहिए।

देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाने वाला किसान एक तरफ तो महँगाई की मार से खुदी परेशान है, उसी में सरकार का यह फरमान कि पराली फूंकने पर किसानों को आर्थिक दंड, उनकी आमदनी पर सीधा डाका डालना हुआ ना। एक तो धान की खरीद औनेपौने दाम पर हो रही है, जिससे कि धान के फसल की लागत ही निकल पाए, मुश्किल लगता है, ऊपर से किसानों पर इस तरह का प्रतिबंध ठीक नहीं लगता। पर्यावरण प्रदूषण का ग्राफ तो अन्य सेक्टरों से भी बढ़ रहा है, उन पर भी तो प्रतिबंध जरूरी है, उन पर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाए और जितनी तेजी व शक्ति से किसानों के ऊपर यह लागू किया गया, अन्य किसी सेक्टरों में तो यह देखने को नहीं मिलता। किसान कमजोर है, इसीलिए ऐसा हुआ आदेश के नाम पर आर्थिक वसूली धड़ल्ले से किया जा रहा है, आखिर यह क्या है? सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण क्या महज किसानों की ही जिम्मेदारी है, अन्य किसी का नहीं! परिवहन, कल कारखानें व नगरीय कचरे क्या पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दे रहें? इन पर भी आर्थिक जुर्माना व पूर्ण प्रतिबंध तो नहीं देखा गया कभी, क्या ये सेक्टर दोषी नहीं हैं? हर तरफ से किसान को ही क्यों लूटा और दबाया जा रहा है आखिर? किसान ही तो पर्यावरण का एक अकेला दुश्मन नहीं! धान की पराली जलाने न जला पाने से, आगामी गेहूँ के फसल का उत्पादन भी घटने की पूरीपूरी उम्मीद है, क्योंकि धान की पराली के साथ खेत की जुताई अच्छे से संभव नहीं हो पा रही है। माननीय उच्च न्यायालय और सरकार के इस दिशानिर्देश का पालन प्रशासन बहुत तीव्र गति से कर रहा है, क्योंकि इससे सक्रियता भी बनी हुई है और जेबें भी गरम हो रही हैं। प्रशासन के इस वर्ताव पर सरकार का संज्ञान न लेना, किसान के मन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर किसान परेशान होगा तो राजनीति जरूर प्रभावित होगी। अतः सरकार से उम्मीद है कि इस बात पर गौर जरूर करेंगे क्योंकि प्रतिबंध ठीक है, मगर किसानों के साथ अवैधानिक आर्थिक वसूली बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है।

मिथलेश सिंह मिलिंद
आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
www.womenexpress.in

गरीबों की दुआ ले लो

खुशी एक पल की दे दो या
दुख उनके जरा ले लो
कभी मौका मिले सेवा का तो
उसको सदा ले लो
अगर उनकी दुआ मिलती है तो
भगवान मिलते हैं
कभी चूको नहीं हरदम गरीबों
की दुआ ले लो

सहारा उनको दे दो जो यहां पर
बेसहारे हैं
नहीं उनका है कोई दोष वे
किस्मत के मारे हैं
भले दृष्टि को करके हीन
दुनिया देखती उनको
मगर भगवान की नजरों में वे
सब दुलारे हैं
उनको मान दे भगवन के
चरणों में जगह ले लो
कभी चूको नहीं हरदम गरीबों
की दुआ ले लो

सभी के हाल तय करती हुई
किस्मत की है रेखा
होता जो यहां पर है वो बस है
भाग्य का लेखा
कभी इतराना या मायूस न
हालात पर होना
पल में ही बदलता सब है कल
किसने है देखा
अगर सुख आज है भोगो, दुख
का भी मजा ले लो
कभी चूको नहीं हरदम गरीबों
की दुआ ले लो

विक्रम कुमार
मनोरा, वैशाली
www.womenexpress.in

सरस्वती वंदना

हे ! मां सरस्वती जी श्वेत
वस्त्र धारणी,
शत् शत् नमन करता हूं सुबह शाम।
हंसों पर सवारी करती है
वीणापाणि,
सभी के बना देती है बिगड़े काम।।

कमलासन पर विराजमान होती
है मां,
कानों में कुंडल मस्तक सिंदूर
चार भुजा धारी।
गले में विराजमान होकर सभी
को ज्ञान देती है,
वीणापानी सभी की रक्षा करती
है प्यारी प्यारी।।
मन के अंधेरी मिटाने वाली
मां हंस वाहिनी,
मां रग रग में सभी के वास
करती हो।
सबको बांटती है ज्ञान भंडार
मां शारदा,
सभी भक्तों की हृदय में ज्ञान
की झोली भरती हो।।

मस्तक में मां के कुमकुम
रोली का तिलक लगाएं,
श्रद्धा सुमन के गले में हार पहनाएं।
जगमग जगमग मां की दीप जलाएं,
मां की चरणों में हम सब
शीश झुकाए।।

हे ! सरस्वती मां प्रार्थना करते हम,
शारदे अज्ञानता से हमें तार
दीजिए। अवगुणों को दूर भगा कर
मां भगवती,
हम सबका विनती स्वीकार
कर लीजिए।।

देवीदीन चंद्रवंशी
अनूपपुर (मध्यप्रदेश)।
www.womenexpress.in

देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह...!

देवउठनी एकादशी, पर्व
कार्तिक मास।
भारत की भूमि धरा, पूजन
करते ख़ास।
श्रीविष्णुजी कृपा करें, क्षीरसागर
त वास।
कार्तिक की एकादशी, देव उठे
जे मास।
मंगल काम विवाह का, तुलसी
त शालिग्राम।
पुण्य प्रताप भी मिले, सफल
होय सब काम।
मनकी पूरन कामना, काम
सिद्ध सब होय।
देवउत्थान एकादशी, पुण्यफलदाय कोय।
शालिग्राम त रूप विष्णु,
श्रापमुक्ति अवतार।
तुलसी क्रोध भयंकरा,
विष्णुशिला आकार।
शालिग्राम रूप धरा,तुलसी
विवाह कोय।
जेहि मुक्त श्रापित किया,जुग
जुग जग की होय।
महिमा जिनकी जग जपे,तुलसी
जपे महान।
तुलसी जिस घर में बसे, घर
मंदिर समान।
देवउठनी एकादशी, पूजत सब
जो काज।
प्राण निशदिन रक्षा करें, दूर रहे यमराज।
शदियों जहाँ प्रथा चला,मन में
रखयो आस।
जाके मन में हरि बसे, हरि
जाके ते पास।
जगमग रोशन जग भया, तुलसी
माता नाम।
श्रद्धा मन बसे भावना, पूरन हो
सब काम।
सुख संवृद्धि भरा भरा, धन की
बरसा होय।
अथाह भक्ति उपज जहाँ,
तुलसी पूजन कोय।
देवउठनी एकादशी, तुलसी मात प्रमान।
कोटि कोटि बन्दन करूँ,रखियो
मोरे मान।

दिव्यानंद पटेल
विद्युत नगर दर्री
कोरबा, छत्तीसगढ़।
www.womenexpress.in

आखें खोलो

आशा भरी निगाहों से
सब देख रहे हैं तुमको ही
ओ नन्हे परिंदे आखें खोलो!

तमन्नाओं के बगीचे से
गुलशन देख रहा तुमको
छोटी सी कली आखें खोलो!

दुआओं के दर से देखो
हाथ जुड़े हैं तुम्हारे लिए
मेरे छोटे कान्हा आखें खोलो!

हर ममता तुम पर न्योछावर
जननी की खुशियों के लिए
हे प्यारे पुत्र तुम आखें खोलो!

मीना सामंत
एमबी रोड, नई दिल्ली।
www.womenexpress.in

मिनखपणे रा ढोंग

केरल में अेक हथनी ने खाणा रे बदले
घाल द्यो विस्फोटक
जल गयो उणरो मुंड़ो;
खा नी सके खाणों
सैसूं मोटी बात तो आ क;
बच्चों वी रै पेट मायं
इण दुख सूं बापडां घणकरा रे;
काळजे घाव पडिया
दया रा बादळा फूट र नदियाँ बणगी;
अर नदियाँ रा रेळा फैल गया;
अेक सागर ज्यूं सगळे देस में;
आन्दोलन रै रूप मायं
किकण सै न कर सके;
अे मिनखपणे रा भगत;
अेक जिनावर री हत्या;
वी रे टाबर री भ्रूणहत्या
ममता दिखावण खातर;
बे हुआ घणा खाथा;
मिनख रो गळो काटण
पण इणीज पाण रोज व्है विस्फोट
म्हारे माथै जात रै बंब सूं;
कर न्हाखै लीरा लीरा काळजो म्हारों
लुगाइया नी बैठ सके
फटफटिया माथै
भले है उणरे आवण जापो
लारै बैठोड़ी लुगाई ने;
गिरा न्हाखै जात री राड़ सूं
मर ज्यावे उणा री ममता;
कर न्हाखै भ्रूणहत्या
पोळ रे साम्ही सूं नी जा सके;
चप्पल पैर लुगाइयाँ
जावती रे ऊपर न्हाखै छांटा;
गाळियां रा; ओछी जात रा
उण बखत अे भगत;
बण ज्यावे जिनावर;
मिनख रै खातर
ताळो लगा र मुंड़ा माथै;
बण ज्यावे आँधा आँख्यां सू
अे फकत ढोंग करे; मिनखपणे

जिनावर खातर
चरली (आहोर) राजस्थान।
www.womenexpress.in

मुश्किलें जिसको डरा दे, है वह कैसा मुसाफिर

मुश्किलें जिसको डरा दे, है
वह कैसा मुसाफिर
जिसको थका दे शूल पथ, है
वह कैसा मुसाफिर

हौसला वह क्या जिसे, कुछ
आंधियां पीछे हटा दे
ध्येय पथ के पंथी को, पथ से
अपने ही डिगा दे

मुस्कुरा कर चल मुसाफिर,
तुझको ही बढ़ना पड़ेगा
आंधियों के अंधड़ों से,
अविचल हो लड़ना पड़ेगा
सामने पहाड़ हो या मरू तुझको
है चलना
झुलसती गर्मी में तप कर, सर्द
रातों में है गलना

मौत मिल जाए अगर, तो तुझे
भिड़ना पड़ेगा
हे मुसाफिर कंटको का, सामना
करना पड़ेगा

शूल पथ के ना हटेंगे, धैर्य धर
कर पार कर
पांव की पीड़ा क्षणिक यह,
लक्ष्य पर ही ध्यान धर

भावना यदि जीत की तो,
मुस्कुराता चल मुसाफिर
जिंदगी की जंग में, नित विजय
तू कर मुसाफिर

निलेश जोशी
बाली, पाली, राजस्थान।
www.womenexpress.in

ऐसा होता है प्रेम

दिल जब अपनाता है किसी को,
तो चाहता है उनसे मुलाकातें।
मन ही मन करता है मन,
प्रेम भरी मधुरमधुर बातें।
ऐसा होता है प्रेम ।।

काँटा चुभे पैर में, तो रो देती हैं आँखें ।
आए प्रिय पर संकट ,
बढ़ जाती हमारी साँसें।
ऐसा होता है प्रेम ।।
फूलफूल मँडराता भँवरा,
बिसरकर सुधि अपने तन की।
पराग कणों से प्रेम की खातिर,
साँसे गँवाता निज जीवन की।
ऐसा होता है प्रेम ।।

नव मास सहती माँ, कष्ट और पीड़ाएँ।
जन्मते ही शिशु के,
लूटाने लगती भावनाएँ।
ऐसा होता है प्रेम ।।
मौन भाव की होती है,
यह समझ बड़ी गहरी।
आशा की हो जैसे ,
कोई किरण सुनहरी ।
ऐसा होता हे प्रेम ।।

निस्वार्थ भाव के होते हैं, प्रेम के धागे ।
समर्पित सब कुछ, पर कुछ ना माँगे।
ऐसा होता है प्रेम ।।
ऐसा होता है प्रेम ।।

ममता शर्मा
अलीराजपुर, मध्य प्रदेश।
www.womenexpress.in

वो दिन कमाल के थे

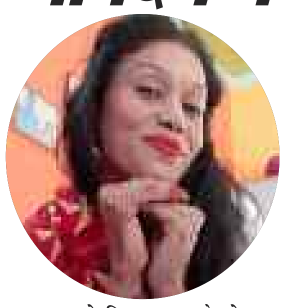

वो दिन कमाल के थे
ना फ़िक्र खाने की ना फ़िक्र
कमाने की वो दिन कमाल के थे

ना बंदिशे समाज की ना
परवाह लोक लाज की वो दिन
कमाल के थे

ना बोझ गृहस्थी का ना और
एक पर से घूमना बस्ती बस्ती का
वो दिन कमाल के थे

जेब हो खाली मगर दिल की गुल्लक
भरी हुई वो दिन कमाल के थे
Tv, mobile , pubjii
छोड़कर सुनना किस्से कहानियां वो
दिन कमाल के थे

एक चौपाल और सुनना पास
पड़ोसियों का हाल वो दिन कमाल के थे

घर बड़े नही थे मगर दिल बड़े
थे वो दिन कमाल के थे
बिन **security** रोके जाकर
देखना रामायण और महाभारत वो
दिन कमाल के थे

Online सीख और भूल गुरू
को वो दिन कमाल के थे

सीमा तोमर
ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश।
www.womenexpress.in

सर्दी का मौसम आया है

सर्दी का मौसम आया है
ठण्ड और कोहरे ने जाल
बिछाया है
सब रहते ठिठुरते सर्दी से
कूलर छोड़ हीटर लगाया है
खाते हैं लोग बड़े, बहुत ही कुछ
तब जाकर सर्दी से थोड़ा
आराम पाया है
कंबल, रजाई ओढ़ और स्वाटर पहन
ठण्ड से थोड़ा चैन पाया है

लेकिन इस शीत लहर ने दूसरी तरफ
गरीबों को बड़ा ही सताया है
जिनके पास ना घर, ना ही,
सूट और बूट
उनके लिए बनकर दुश्मन ये
आया है
उनके लिए बन दुश्मन ये
मौसम आया है

करमजीत कौर
श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब।
www.womenexpress.in

स्मृतियों के अवशेष

स्मृति पटल पर अंकित हैं
अभी भी स्मृतियों के अवशेष,
जीवन सरिता बनती है
जिनसे उज्जवल और विशेष

जीवन मूल्यों को
विस्मृत ना होने दिया
बांधा मैंने आंचल में
उनको ना खोने दिया

बन गया धरोहर जाने कब
बचपन बहुमूल्य हो गया,
स्मृति खजाने में जा
वहीं सुरक्षित हो गया, कालचक्र
में फंसकर
कुछ तो पीछे छूट गया,
वो समय सुनहरी यादों का जैसे
कुछ रूठ गया

मार्गदर्शक बनते हैं आज भी मातपिता,
शिक्षाएं उनकी दिखाती
आज भी रास्ता

खट्टे मीठे पलों को जीवंत कर
जाएं कभी, मस्तिष्क में उठती तरंगे
स्वप्न दिखलायें कभी

दुख कड़वाहट के क्षण विस्मृत
हो जाए तो अच्छा,
सुखद अनुभवों को
स्मृतियों में लाएं तो अच्छा

स्मृति पटल पर अंकित हैं अभी
भी स्मृतियों के अवशेष,
जीवन सरिता बनती है
जिनसे उज्जवल और विशेष

शालिनी शर्मा
इटावा, उत्तर प्रदेश।
www.womenexpress.in

देवउठनी एकादशी का पर्व

माता तुलसी विष्णु का
होता,शुभ विवाह का काज।
चौमासा शयन पश्चात,जागे
विष्णु भगवान आज।
शालिग्राम संग तुलसी पौधा का
विवाह कर पर्व ।
देवोत्थान ग्यारस का व्रत मनाते
एकादशी पर नाज।।
कार्तिक शुक्ल एकादशी को
आता शुभ त्यौहार।
आषाढ़ शुक्ल एकादशी को
जाते प्रभु समुद्र सार।
चौमास के शयन पश्चात आता
ये मांगलिक पर्व।
लक्ष्मीनारायण की पूजाकर
मनाते देवप्रबोधिनी त्यौहार।।
जागो जागो हे प्रभु
जगतपालक, निद्रा से जागो।
चौमास बीती अब खि़रसागर
के बंधन को त्यागो।
हजार अश्वमेघ व सौ राजसूय
यज्ञ का फल है मिलता।
देवोत्थान एकादशी का व्रत का
आवाहन फल साजो ।

सुन्दर लाल डडसेना
महासमुंद (छत्तीसगढ़)।
www.womenexpress.in

लघुकथा- वर्जपात

सब जलके राख होई गयो रे ,सब जलके राख होई गयो रे,महारो आदमी भी चलो गयो।बस रो रो के यही बोल रही थी लीलीबाई।उफ्फ्फ उसकी आंसूओं और वेदना देख मे भी खुद के आंसूओं को रोक ना पाई आज मैं चाहे एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं पर हूं लीली का पति जब मौसम ने एकाएक करवट ली और बादलों की अलहड़ मस्ती,लड़ाई,टकराव संग बिजली की नज़ाकत कह लो या शरारत,आके गीर पड़ी लीला के खेत मे लील गई पूरा लीला का खेत और उसमें काम कर रहे उस समय पांच लोगों मे से तीन लोगों को जिसमें एक लीला का भी पति था।आज लीला के ऊपर ही जैसे वर्जपात गिर गया हो उसकी दो बेटियां जिसमें से बड़ी की अगले महीने शादी है कैसे करेगी इन दुखों के पहाड़ के बीच लीला अपनी बेटी की शादी सच आज खुद की भीतरी वेदना को रोकना चाही पर न रोक सकी मैं और मात्र कल्पना से सिहर उठी की यदि ये सब हममें से किसी के साथ हो तो? किसानों के साथ अकसर ये हादसे होते रहते हैं जिनका एकमात्र सहारा कभी कभी प्राकृतिक घटनाओं की बलि भी चढ़ जाता है।

वीना आडवानी
नागपुर, महाराष्ट्र।
www.womenexpress.in

माता पिता के नाम संदेश

बेटी को कहते हैं सब अनमोल
बेटे के बराबर इसको भी तो
दो मोल
बेटी बेटा को भेजो एक ही स्कूल
इसमें क्यों करते हो तोल मोल
बेटे को तो मिलें मौके हजार
जरा बेटी का भी रखो खयाल
क्यों बनाये बेटा कैरियर
और बेटी जाये ससुराल

मां बेटे की बुराइयां तो बाप से
छुपाती
क्यों स्त्री ही स्त्री से भेदभाव
करवाती
ये कैसी है मां की ममता
खुद की बेटी को भी उसका
हक ना दिलवा पाती
उसे भी अपनी मर्जी से जीने दो
मत रखो कोई बंधन

बेटे की तरह उसे भी पहनने दो
मर्जी के परिधान
फिर भले कहो गर्व से बेटा
बेटी एकसमान
वो ख्वाहिश भी करो पूरी जो
कभी ना वो कह पाये
लोग क्या कहेंगे ये बंधन सारे
तोड़कर

बेटी को जो दे इक पहचान
जग में वही है मात पिता महान
तुम तो बने सिर्फ उसकी ताकत
वो खुदबखुद बना लेगी अपनी
पहचान

दीप
हनुमानगढ, राजस्थान।
www.womenexpress.in

रौशनी का शहर

रोशनी के शहर में कुछ गुम हो
गये है रिश्ते,
आज फिर मैंने देखा है।
अपनी यादों की संदूकची की
आज फिर टटोलने की कोशिश की
कुछ फटे,कुछ पुराने,कुछ
गोटा,कोई ज़री थी
कुछ मलमल था,कोई सादा था।
जाने कब से कुछ रिश्ते शहर
में बंद पड़े है
कितना जोड़ूँ,कितना सीलूँ कुछ
को तो रफ्फू भी कर लूँ
कितने रिश्ते उधड़ गये हैं
रंग बिरंगे धागे से मैं तो
उसमें कोई कसीदा कर दुँ।
किसी में मोती डाल भी दुँ
किसी में नया आवरण चढ़ा दुँ।
सालों से सहेज कर रिश्तो को
रखनी है सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी
रौशनी से भरा शहर है,
सब सब से बेख़बर है
चकाचौंध से भरी ये दुनिया
नही खबर है उनको मेरी
शायद रिश्तो में ही कमज़ोरी
कुछ तो बसते जंगल में,
होती घर आंगन जैसी दूरी।
हम तो दुश्मन है उनके,
कहाँ खबर है उनको मेरी।
सदियों से होता आया है,
बात बात से बढ़ती दूरी
क्या ऐसा हमसे पाप हुआ है ?
जो बढ़ गई अपनी इतनी दूरी।
ना जाने कैसा श्राप है
चांद पर भी तो लगा दाग है।
फिर भी चांद पुजा जाता
चौथ के चांद देख मुंह ना फेरो
वही पूर्ण चांद हर घर पूजा जाता।

रानी प्रियंका वल्लरी
बहादुरगढ, हरियाणा।
www.womenexpress.in

सैनिकों की सुरक्षा जरूरी

सैनिकों की सुरक्षा में ही देश की सुरक्षा निहित होती है। जितनी आधुनिकतम सुविधाएं उन्हें मिलेगी उतना ही दृढ़ता के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे सकेंगे। इस समय ठंड का मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीला होना शुरू हो गया है।अभी हालांकि मैदानी क्षेत्र सामान्य है। पहाड़ों पर गश्त देना सैनिकों के यह लिए बड़ा दुष्कर होता है। ऐसे में विशेष परिधानों के साथ ही अत्याधुनिक आवास बनाए जाना सराहनीय है। सरकार को सैनिकों के लिए पहाड़ों पर और अत्यंत जरूरी तमाम साधन उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे सैनिकों का हौसला बना रहे।

इस समय भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है। इसमें हमारे सैनिक दिनरात बर्फीली चोटियों पर पहरा दे कर उन्हें महफूज रख रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में उन्हें विशेष बचाव के साधन जरूरी है। पहले सरकार ने सैनिकों के लिए इजरायल और अमेरिका से विशेष वस्त्रों की खरीदी की है जो सैनिकों को माइनस में खेले जाने वाले तापमान से बचाएगी। दुर्गम क्षेत्रों

में जवानों के लिए अत्याधुनिक आवास बनाएं गए हैं जिनमें 40 डिग्री तापमान में भी वह महफूज रह सकेंगे। पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों में बनाए गए इन आवासों में हर तरह की तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं। करीब 50,000 तैनात जवानों के लिए बिजली, पानी, गर्मी, स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाओं से भरपूर आवासों से सैनिक निश्चिंतता के साथ अपना कर्तव्य निभा सकेंगे। ताजा हालातों के मद्देनजर विवाद का अब कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है ऐसे में सर्दियों में सतर्कता जरूरी है। सुविधाएं मिलने से सैनिक फसलों के साथ मुस्तैद रहकर सीमाओं की रक्षा कर सकेंगे।

अमृतलाल मारू
धार, मध्यप्रदेश।
www.womenexpress.in

यथार्थ के धरातल पर रहते रहते

यथार्थ के धरातल पर रहते रहते,
जीवन की कड़वाहट को सहते सहते।
अब मन करता है सपनों में जीने को,
रास्ते के कंकड़ो को ठोकर लगाने को।
जी चाहता है बादलों में घर बनाऊं,
नीले अंबर पर बैठ कर इठलाऊं।
समंदर के नीले पानी में डूब जाऊं,
गहराई में जाकर धरती को चूम आऊं।

तितली की भांति फूलों पर मड़राऊ,
रंग बिरंगे फूलों की महक में खो जाऊं।
सूर्य की किरणों सा जग में बिखर जाऊं,
चांदनी सी नीशा मे छिटक जाऊं।

न भूख लगे, न ही कभी प्यास लगे,
न ही किसी को पाने की आस लगे।
काश ऐसा भी कोई विकल्प होता,
प्रकृति की निधि मेंयह कल्प होता।

डा शीला चतुर्वेदी,
देवरिया, उत्तर प्रदेश।
www.womenexpress.in

संसार

अनुभूतियों की दहलीज पर,
कलरव करता राग विराग का संसार।
क्षितिज पार नेह ऋचाओं का संगीत,
मृदुल अनुभूतियों का अनूठा संसार।
मन वीणा में पिरोती ,
मेरे अल्फाजों का संसार।
धागे प्रेम के बुन रही हसरतें,
मोहपाश में बंधा मखमली संसार।
मधु, स्नेहिल प्रीत में बंधी स्मृतियां,
स्वप्निल रंगों का सजा अनूठा संसार।
अभिव्यक्ति की प्यासी मधुशाला,
है बेचैन परिधियों में जज्बातों का संसार।

मधु वैष्णव, मान्या
जोधपुर, राजस्थान।
www.womenexpress.in

भारत के खिलाफ श्रृंखला में हार अब भी कचोटती है: पेन

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

सिडनी, 24 नवंबर । आस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने स्वीकार किया है कि भारत के खिलाफ पिछली टेस्ट श्रृंखला में 'कचोटने' वाली हार अब भी उन्हें 'पीड़ा' देती हैं। पेन ने हालांकि कहा कि आस्ट्रेलिया की टीम अब बेहतर आलराउंड टीम है जो भारत से भिड़ने को बेताब है। भारत ने 201819 में आस्ट्रेलिया को 21 से हराकर इस देश में पहली टेस्ट श्रृंखला जीती थी।

यह कप्तान के रूप में पेन की पहली घरेलू श्रृंखला थी। तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर पर 2018 में गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के शामिल होने के कारण एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था जिसके बाद पेन को टीम की कमान सौंपी गई थी। पेन ने 2जीबी के वाइड वर्ल्ड आफ स्पोर्ट्स रेडियो से कहा, ''मैं जब भी इस बारे में सोचता हूं तो निश्चित तौर पर यह कचोटता है

कि हम वह टेस्ट श्रृंखला हार गए।'' उन्होंने कहा, ''स्टीव और डेविड हों या नहीं, आप कोई टेस्ट मैच या टेस्ट श्रृंखला नहीं हारना चाहते जिसमें आप खेल रहे हों, इसलिए इससे मुझे थोड़ी पीड़ा पहुंचती है।'' पैंतीस साल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि इस हार के दौरान टीम का हिस्सा रहे प्रत्येक खिलाड़ी में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा, ''हमारी टीम अब बेहतर आलराउंड टीम है। स्टीव और डेविड के वापस आने से टीम को काफी अनुभवी खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने ढेरों रन बनाए हैं लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि उस टीम में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी में पिछले 18 महीने में सुधार हुआ है और हम काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं।''

भारत ने पिछली टेस्ट श्रृंखला में एडीलेड और मेलबर्न में पहला और तीसरा टेस्ट जीता था जबकि आस्ट्रेलिया ने पर्थ में दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज की थी।

अंतिम मैच ड्रॉ रहा था। पेन ने कहा कि हार उस श्रृंखला में शामिल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी और यहां तक कि वार्नर और स्मिथ भी यह दिखाने को बेताब हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट की श्रृंखला की शुरुआत एडीलेड में 17 दिसंबर से दिनरात्रि मुकाबले के साथ होगी।

इशांत, रोहित शुरुआत के दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल सकेंगे: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 24 नवंबर । तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी के तहत होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में नहीं ख ल सकेंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसम्बर से एडिलेड में होने वाले दिनरात के टेस्ट मैच से हो रही है। वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो ने इस बात की पुष्टि की है। वेबसाइट के मुताबिक दोनों खिलाड़ी अंतिम दो टेस्ट मैचों में खेल सकेंगे। इशांत ने फिटनेस हासिल कर ली है और अब वह सात जनवरी से सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में जगह के हकदार हैं। रिपोर्ट में कहा

गया है कि इशांत को इसके लिए जल्द से जल्द आस्ट्रेलिया पहुंचना होगा। दूसरी ओर, रोहित अभी एनसीए में हैमस्ट्रींग इंजुरी का इलाज करा रहे हैं। रोहित को आईपीएल के 13वें सीजन के दौरान यह चोट लगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित को दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में ही यात्रा की अनुमति मिल सकेगी क्योंकि वह अभी पूरी फिटनेस नहीं हासिल कर सके हैं। रोहित को दो सप्ताह तक रिहैब में रहना होगा और इसके बाद ही उन्हें लेकर एनसीए किसी निर्णय पर पहुंच सकेगा। रोहित अगर 8 दिसम्बर को भी आस्ट्रेलिया रवाना होते हैं तो उन्हें दो सप्ताह के क्वारंटीन में रहना होगा और फिर वह 22 दिसम्बर से ही अभ्यास कर सकेंगे।

धोनी के मेंटॉर रहे देवल सहाय का रांची में 73 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली। भारत को दो बार विश्व कप विजेता बनाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मेंटॉर देवल सहाय का मंगलवार को रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया है। सहाय को रांची में पहली टर्फ पिच तैयार करने का श्रेय जाता है। वह 73 वर्ष के थे। वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और एक बेटे को छोड़ गए हैं। सहाय, जिनका पहला नाम देवब्रत था, लेकिन लोग उन्हें देवल बुलाते थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें नौ अक्टूबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। सहाय के बेटे अभिनव आकाश सहाय ने कहा, घर पर करीब 10 दिन बिताने के बाद, उन्हें फिर से एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कंगना रनौत को सांप्रदायिक ट्वीट मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। सांप्रदायिक ट्वीट के आरोप मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने कंगना को अंतरिम सुरक्षा दे दी है। कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस की एफआईआर रद्द करने की गुजारिश की थी।

ये एफआईआर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई थी। साथ ही कंगना को आठ जनवरी को मुंबई पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कथित रूप से ''घृणा और साम्प्रदायिक तनाव'' फैलाने का आरोप लगाते हुए रंगोली और चंदेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को

मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।

जस्टिस एस. एस. शिंदे और जस्टिस एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने रनौत और चंदेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जिसमें दोनों ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और 17 अक्टूबर के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने तीन सम्मन जारी किए हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। रनौत और चंदेल के वकील रिजवान सिद्दीकी ने इसपर अदालत को आश्वासन दिया कि दोनों बहने अपने बयान के मुताबिक आठ जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक मुंबई में बांद्रा पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगी। अदालत ने उनके इस बयान को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा, ''पहली नजर में हमारा मानना है कि जबतक मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती अंतरिम राहत देना जायज है। पुलिस आवेदकों (रनौत और चंदेल) की गिरफ्तारी के साथसाथ अन्य कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे।''

अदालत ने यह भी जानना चाहा कि इस मामले में राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया गया है। जस्टिस शिंदे ने सवाल किया, ''राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया गया है? हम अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं?'' अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय करते हुए कहा कि वह अगली सुनवाई के दिन इसपर विस्तार से विचार करेगी।

'दिल्ली क्राइम' को एमी में मिला 'बेस्ट ड्रामा सीरीज' का पुरस्कार

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

मुम्बई, 24 नवंबर । 'नेटफ्लिक्स इंडिया' की मूल श्रंखला 'दिल्ली क्राइम' ने 48वें 'इंटरनेशनल एमी अवार्ड' में 'बेस्ट ड्रामा सीरीज' का पुरस्कार अपने नाम किया है। भारतीयकनाडाई रिची मेहता के निर्देशन में बनी वेब श्रंखला दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को पैरामेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना पर आधारित है।

गंभीर रूप से घायल छात्रा ने एक पखवाड़े बाद सिंगापुर में एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कोरोना वायरस के कारण एमी का आयोजन सोमवार को ऑनलाइन किया गया। मेहता ने इस दौरान पुरस्कार उन सभी महिलाओं को समर्पित किया, जो न केवल पुरुषों द्वारा की जाने वाली हिंसा को सहन करती हैं, बल्कि जो समस्या को हल करने के लिए भी काम कर रही हैं।

यह वेब श्रंखला 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग नजर आए थे। इसके अलावा भारत से 'एमेजन प्राइम वीडियो' की श्रंखला 'फोर मोर शॉट्स' ड्रामा और 'मेड इन हेवन' कॉमेडी श्रेणी में नामांकित थी लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई।

उठकर गिरानें के बाद

उठकर गिरानें के बाद ,
उसने उसे कूदकर पार करना चाहा,
पर बीच में ही मुंह के बल गिर गया,
आज उसे अपना गिरना अच्छा लगा,
बहुत गिरने के बनिस्बत,
पहले गिरने पर उठ नहीं पाया था,
बहुत गिर चुका था,
पर अब गिरकर कीचड़ से
लथपथ फिर खड़ा हुआ,
नवजात जानवर के बछड़े की तरह,
बच्चे बहुत नीचे नहीं गिरते,
कोमल मन भावना सच्ची बातें
के चलते, चलते चलते
लड़खड़ाते हैं,
बहुत नहीं गिरते,
गिरना गिरकर उठना उनका
खेल होता है,
पर उसमें अब उठने की चाहत
नहीं रह गई है,
बच्चों से नहीं मिला सकते आंखें,
नई ऊर्जा नए आकाश की तलाश में
फिर उठने की,
बच्चे गिरने के बाद इधरउधर
नहीं देखते
कि कोई देख रहा है क्या,
इस बार वह दलदल में गिरा था,
अपने गिरने पर शर्म को जिया था,
अब वह गिर कर लजाता नहीं,
अब बड़ा हो गया है,
इसलिए गिर चुका है,
शायद बहुत ज्यादा

संजीव ठाकुर
चोबे कोलोनी, रायपुर ।
www.womenexpress.in

मुहब्बत

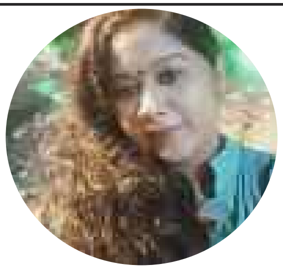

रंज ही सही तू ,
दर्द देने के लिये आ,
मैं भूल जाऊ तुझे, और तू खुद को,
याद दिलाने के लिये आ।
माना अंधेरा घना है,
और राह कठिन, तू छोड़ सारे अंधेरे,
उजाले तू हाँथ थाम,
जग छोड़ने के लिये आ।
रोज रोज तुझे याद करके, थक चुकी हूँ,
की अबकी बार तू सबको,
भुला न जाने के लिये आ।
मैं मर कर भी तेरे,
सजदे में रहूँगी,
तू इस बार बस,
खुदा बनने के लिये आ।

डिम्पल तिवारी, अवध
अयोध्या, उत्तर प्रदेश ।
www.womenexpress.in

दुख दर्द कहाँ ठहरे हैं

क्या हुआ तुझपे आज गम के
पहरे हैं।
कब कहाँ दुख दर्द ज्यादा दिन
ठहरे हैं ।।
सबसे बुराइयां सुन के चुप रहता हूँ,
लोग समझते हैं कि कान मेरे बहरे हैं ।
गैरों ने सताया उसकी क्या बात करें,
जो दिये अपनों ने जख्म बड़े गहरे हैं।
सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और,
यहां कुछ लोगों के दो तरह के
चेहरे हैं ।
मेरे अरमाँ के परिंदों की उड़ान ऊंची है,
छूना है मुझे फलक मेरे सपने सुनहरे हैं ।
साहिल पे मेरी कश्ती जरूर आ
के रहेगी,
क्या हुआ कठिन दरिया
उफनती लहरें हैं ।
जुगनू भी कभी राह में दिखा
देता है रास्ता,
हिम्मत न हार जो सफर में
घने कोहरे हैं ।
शतरंज का खिलाड़ी ऊपर कहीं बैठा है,
हम सभी तो जमीं पे फकत
एक मोहरे हैं ।

एस पी दीक्षित
शुक्लागंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश ।
www.womenexpress.in

सत्य ही जीतेगा

अहंकार में मत इठलाओ
राजा नहीं जनप्रतिनिधि हो
इतिहासों को पलट कर देखो
त्रेता युग हो या द्वापर युग हो
सत्य हमेशा ही विजयी रहा
सत्तामद में पागल होकर ही
भ्रष्टाचारी जैसा व्यवहार हुआ
सत्य को कुचलने का षड़यंत्र
जनता को सब दिख रहा
शोषण की सीमा पार हुई
जनता जब विद्रोह पर उतरी
सत्ता तेरी उजड़ जायेगी
अहंकार और वजूद तेरा भी
सब मिट्टी में मिल जायेगें
सत्य कोई मिटा न पाया है
सत्य ही जीता है जीतेगा ।

शिवनन्दन सिंह
जमशेदपुर, झारखण्ड।

मदद के पंख कैसे जलते

दुःख की परिभाषा भूखे से पूछो
या जिनके पास पैसा नहीं हो
उससे पूछों।
अस्पताल में बीमार के परिजन से पूछों
बच्चों की फ़ीस भरने का
इंतजाम करने वालों से पूछों
लड़की की शादी के लिए
इंतजाम करने वालों से पूछों।
जब ऐसे इंतजाम सर पर आ खड़े हो
कविताएं अपनी खोल में जा
दुबक कर
मैदानी मुकाबले किताबी अक्षरों में
हो जाती बेसुध ।
मदद की कविता जब अपनों
से गुहार करती
तब मदद के पंख या तो जल
जाते या फिर कट जाते।
क्या ता उम्र तक इंसान ऋृणी के रोग से
पीड़ित होता
हाँ , होता है ये सच है।
क्योंकि सच हमेशा कड़वा
और सच होता
अपने भी मुँह मोड़ लेते।
ये भी सच है की इंसान के पास
पैसा होना चाहिए
पूछ परख होती
पैसा है तो इंसान की पूछ परख
नहीं तो मदददगार पहले ही
भिखारी का भेष
पहनकर घूमते।
पैसा है तो आपकी वखत
नहीं तो रिश्ते भी बैसाखियों पर
टिक जाते ।
दुनिया में इंसान ने अपनी राह
स्वयं को चुनना
सलाह सब की मगर करना मन की।
नहीं तो कर्ज की गर्त में
दुखों से खुशियों को निकलते
किसी ने
आज तक नहीं देखा ।
भाग्य के ख्वाब बस सपनों तक ही
सिमित क्योकि कर्ज देना स्वयं
को देना
और उधार मांगने वक्त
लोग आपसे भी गरीब बन जाते है ।
बस सोच ये रखना
जितनी चादर उतने पांव पसारना।

संजय वर्मा
धार, मध्यप्रदेश ।
www.womenexpress.in

सदा महकता निर्झर

झर झर अविरल झरता निर्झर।
सर सर अविरत बहता निर्झर।।
सदा प्रवाहित प्रमुदित पथ में।
कलरव करता रहता निर्झर।।
प्रस्तर से टकराता प्रतिपल।

मन की पीर न कहता निर्झर।।
परसुख में निज खुशी मनाता।
हरदम कंटक सहता निर्झर।।

नाना औषधि जल में घुलतीं।
सदा महकता रहता निर्झर।।
यह जाने सीमा की मर्यादा ।
पथ से नहीं बहकता निर्झर।।
सदा पिलाकर शीतल मृदु जल।
थकनतपन सब हरता निर्झर।।
सतत चलो का संदेश सुना।
उर उमंग नित भरता निर्झर।।

प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा, उत्तर प्रदेश ।
www.womenexpress.in

राष्ट्रकवि दिनकर

दिनकर ऐसा सूर्य है जिसने
हिन्दी जगत को अपनी लेखनी की
किरणों से चमकाया
देशहित में लिखकर
देश का गौरव खूब बढ़ाया
जिनके सूर्यातप के आगे
शशि भी मलिन हो जाए
ऐसे राष्ट्रकवि को प्रज्ञा
शीश नवाए
हिन्दी की खड़ी बोली का गौरव
दिनकर ने खूब बढ़ाया
उर्वशी लिखकर दिनकर जी ने
हिन्दी साहित्य को एक रत्न चढ़ाया
मीठी सरल, सरस भाषा में
दिनकर जी लिखते थे
पीड़ितों के दर्द को अपने
काव्य में स्वर देते थे
राष्ट्र चेतना जगाकर कवि ने
विश्व में ख्याति है पाई
बाल साहित्य और गद्यप
दोनों विधा अपनाई
पद्मविभूषण और मिला
ज्ञानपीठ पुरस्कार
रामधारी सिंह दिनकर को
जन्म दिवस पर हम सबका नमस्कार...

प्रज्ञा शुक्ला
सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
www.womenexpress.in

वर्तमान परिवेश में शिक्षा

ऑनलाइन गुरु, प्राचीन काल से लेकर अब तक शिक्षा व्यवस्था ने कई रूप बदले, आश्रम से लेकर स्कूल तक परिवर्तन के कई सोपान चढ़े। और अब स्कूल और कॉलेज से मोबाइल व कंप्यूटर की स्क्रीन तक का सफर। परिवर्तन समय की मांग है, और हर परिवर्तन को विरोध का सामना करना पड़ता है।

किंतु एक सच यह भी है कि परिवर्तन ही विकास की आधारशिला है। तमाम समस्याओं के होते हुए भी अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव दिखने लगे हैं। जिस तकनीकी विकास व आईसीटी के स्वाभाविक उपयोग के लिए शायद हमें कई वर्ष लग जाते, कोविड19 की आपदा से यह अचानक ही लोगों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया।

अब जरूरत है इस ऑनलाइन गुरु की भूमिका तय करने की, क्योंकि कितना भी समय बदल जाए एक शिक्षक का स्थान और उसकी जरूरत तो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि कब जानना है ,और कितना जानना है , का मार्गदर्शन तो एक शिक्षक ही कर सकता है।

उसका सानिध्य और वात्सल्य छात्रों को पाठ्यक्रम के अलावा जीवन जीने के तरीके भी अनायास ही सिखा जाता है। अब इस चुनौतीपूर्ण माहौल में शिक्षक को बस अपना स्वरूप बदलना है, खुद को अपडेट करना है, और जुड़े रहना है उन्हीं छात्रों के साथ, जिन्हें इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑनलाइन वीडियोस ,क्लासेस ,पावर पॉइंट, और डिजिटल माध्यम का आज इस तरह से उपयोग किया जा रहा है ,उसने शिक्षक को अब केवल गुरु नहीं ,ऑनलाइन गुरु बना दिया है।और यह साबित कर दिया है कि आज का शिक्षक स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ एवं तत्पर है। ऑनलाइन गुरु के रूप में भी।

भावना शर्मा
सहायक अध्यापिका
खान कॉलोनी, छिंदवाड़ा ।
www.womenexpress.in

आभासी दुनिया का प्यार

उमा बी.एस.सी में पढ़ने वाली एक समझदार व सुलझी हुई लड़की थी ।उसे पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज में दिलचस्पी नही थी ।वह हमेशा अपनी किताबों में ही खोई रहती ।कालेज में भी उसके अधिक दोस्त नही थे ।ज्यादातर उसे किताबी कीड़ा और नकचढ़ी कहकर संबोधित करते।उसके ही कालेज में राज नाम एक लड़का पढ़ता था जो स्वयं भी गंभीर प्रवृत्ति का पढ़ाई में बहुत अच्छा था ।स्मार्ट था कई लड़कियाँ दिवानी थी उसकी परंतु वह किसी से भी बात नही करता था ।उसे तो मन ही मन उमा भा गई थी ।परंतु समस्या थी कि बात कैसे की जाए ।एक दिन उसने अपने एक दोस्त की सहायता से उमा से बात करने की कोशिश की परंतु उमा ने कोई प्रतिक्रिया नही दी ।कुछ दिन बाद किसी विषय की जानकारी के लिए उसे राज से बात करनी पढ़ गई और नोट्स लेने की आवश्यकता पड़ गई ।

राज ने उमा को अपना न. दिया कि मैं तुम्हें नोट्स मैसेज कर दूंगा और अगले दिन से ही पढ़ाई का सिलसिला फोन पर शुरू हो गया।दोनों पढ़ाई के अलावा कुछ और बात नही किया करते थे ।परंतु राज उमा को पसंद करता था और खूश था कि पढ़ाई के माध्यम से ही कम से उमा से बात तो होती है ।दो साल ऐसे ही बीत गए ।फिर एक दिन राज ने हिम्मत करके फोन पर उमा से अपने प्यार का इजहार किया।

उमा ने गंभीरता पूर्वक राज से सिर्फ एक ही बात कही की तुम पहले अपना करियर बनाओ उसके बाद ये सब करना ।राज ने उमा से दो वर्ष का समय मांगा और फाइनल पेपर के बाद उमा और राज का कोई संम्पर्क नही रहा। एक वर्ष कब बीत गया पता ही नही चला । एक दिन उमा के फोन पर मेसेज आता है जिसे देख उमा के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान छा जाती है और वो मेसेज किसी और का नही ब्लकि राज का था जो आज नेवी में अधिकारी के रूप में कार्यरत हो चुका था । उसने उमा को धन्यवाद के साथसाथ उसका प्रेम स्वीकार करने की अनुमति मांगी।उमा यह सोचकर हैरान थी कि क्या आज के समय में आभासी दुनिया के झूठे प्रेम वादों के बीच सच्चा प्रेम मायने रखता है । उमा और राज दोनों ने घरवालों की रजामंदी से शादी की और सुखी वैवाहिक जीवन का आंदन ले रहे हैं ।

मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज लड़केलड़कियाँ आभासी दुनिया के प्रेम में संलग्न होकर अपने केरियर, पढ़ाईलिखाई अपने आप की इज्ज़त तक को दांव पर लगा देते हैं । ऐसा मत करिए पहले अपने आप को काबिल बनाइए उसके बाद आपको जो करना है किजिए परंतु एक दायरे में रहकर जिससे किसी को ठेस न पहुँचे।

रश्मि वत्स
मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
www.womenexpress.in

आंसू की नहीं कोई जुबां

आंसू की नहीं कोई ज़ुबां ,
बेज़ुबां होकर भी कह देते सारी
दास्तां ।
कभी ये होते खुशी के , कभी
ग़म के , तो कभी कहते इन्हें लोग
मगरमच्छी आंसु ।
बह जाते जो आंसु बन जाते
वो खारा पानी , जो दफ़न हो जाए
आंखों में ,
वो दिल में बना देते एक
तुफानी कहानी ।
हो किसी का जन्म तो देख
जन्मते बच्चे को परिवार की आंखों
से बहते खुशी के आंसु ,
हो कोई मृत्यु तो विरह में
आंसू से भर जाते नयन ।
औलाद की आंख से गिरा ग़र
आंसू , मां के भी थम नहीं सकते
आंसू ।
अगर रहे पलकों पे तो रूक
नहीं सकते आंसू , बह कर दरिया
बना देते आंसू ।
लगे बच्चे को भूख तो निकल
आते आंसू ,
लगे कोई चोट तो भी बह जाते
आंसू ।
ना हो ज़िद पूरी तो भी आते
आंसू ।
जब दिल सहे ना जुदाई यार
की तो कहानी कह जाते आंसू ,
किसी को देखकर दुखी , दु-
ख के आते आंसू ।
हो जाए गलती कोई तो
पश्चाताप के कहलाते आंसू ,
दिल की सच्चाई बयां करते
आंसू ,रूठे सजन को मनाते आंसू ,
पराए को भी पल में अपनेपन
का एहसास कराते आंसू ।
हो जाए जब कामना पूरी तो
संतुष्टि दे जाते आंसू ।
आंसू ना देखे नर मादा , ना
देखे बुढ़ा जवान , इसे ना आए
नज़र गरीब अमीर ,
ना करें ये किसी पे रहम ,
इसकी सबमें एक जैसी पहचान ।
यारों आंसू तो है आंसू , एक
ही रंग और रूप लिए है आंसू।
नहीं कोई छल कपट रखते
आंसू , बहुत ही मासूम होते आंसू ।

प्रेम बजाज,
यमुनानगर, हरियाणा ।
www.womenexpress.in

पता है, सबसे बुरा क्या है??

भीड़ में होकर भी अकेला होना।
सबके साथ होते हुए भी गुम रहना,
हँसते हँसते अचानक ख़ामोश हो जाना
सिर्फ सोचते जाना, सोचते ही जाना!
ज़ख़्म दुखते हैं तो खुद ही
सहला देती हूँ,
आईना देखकर दिल को
बहला लेती हूँ
उम्मीद सिर्फ़ खुद से है,ग़ैरों से नहीं
बर्फ हैं खुशियाँ, मैं पिघला लेती हूँ!

श्वेता सक्सेना
मालवीय नगर,
जयपुर ।

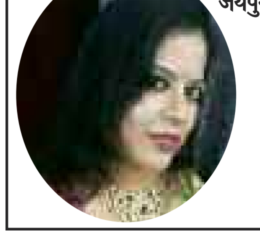

एक नजर

नशामुक्त गांव इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज

देवबंद (सहारनपुर)। सात्विक खानपान और पूर्ण रूप से नशाबंदी का पालन करने वाला देवबंद क्षेत्र का विख्यात और अनूठा गांव मिरगपुर इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज हो गया है। ग्राम मिरगपुर सेवा समिति के सदस्यों मनोज पंवार, अंकुर पंवार चैधरी और रवि पंवार चैधरी ने कहा कि इंडिया बुक आफ रिकार्ड में गांव का नाम दर्ज होने से इस गांव को पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किए जाने में मदद मिल सकती है। करीब 10 हजार की आबादी वाला मिरगपुर गांव देवबंद से पांच किलोमीटर की दूरी पर काली नदी के किनारे पर स्थित है। इस गांव में सात्विक खानपान और नशामुक्ति का अभियान 500 सालों से जारी है। पुष्कर के पास से इंदरपुर से हरिद्वार भ्रमण को आए थे और वापसी में ग्राम मिरगपुर में ऊंचे टीले पर कुटी बनाकर रहे थे।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर 15 पुलिस चौकियां बनेंगी

मंत्रिपरिषद ने यातायात सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकियों की स्थापना को दी मंजूरी

(विशेष संवाददाता)

लखनऊ, 24 नवम्बर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा एवं यातायात सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार 15 पुलिस चौकियां स्थापित करने जा रहा है। ज्ञातव्य है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यातायात की सुरक्षा हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में 03 जून, 2017 को सम्पन्न बैठक में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के आर0ओ0डब्लू0 में पुलिस विभाग एवं यूपीडा के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षणोपरान्त चयनित 21 स्थलों को पुलिस चैकी निर्माण हेतु चिन्हित किया गया, जिसमें से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चैकियों के निर्माण का निर्णय यूपीडा द्वारा लिया गया। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मामले में समयसमय पर कार्यवाही की गई है, जिसमें कार्यदायी संस्था नामित किया जाना, पी0एफ0ए0डी0 से आगणन मूल्यांकन एवं वित्तीय स्वीकृति आदि समयसमय पर निर्गत की गयी है।

पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट व्यवस्था है। इन पुलिस चैकियों से संबंधित स्थलों के भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख (खसरा व खतौनी आदि) यूपीडा के पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये। यातायात सुरक्षा के संबंध में गठित उच्चाधिकार समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं में यह बिन्दु भी है कि एक्सप्रेसवे पर कतिपय घटित लूट की घटनाओं के दृष्टिगत यमुना एक्सप्रेसवे एवं आगरा एक्सप्रेस वे पर यथा आवश्यक पुलिस चैकियां

स्थापित की जाये।

यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आगरालखनऊ एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्था (उ0प्र0जल निगम) व यूपीडा द्वारा निर्मित करायी जा रही 05 पुलिस चैकियां निर्माणाधीन हैं, इनको पूर्ण कराने के उपरान्त, इन 05 पुलिस चैकियों के भूमि/निर्मित भवन को पुलिस चैकियों की स्थापना हेतु गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित ;पूजी जपजसम वर्ा संदकद्ध निरूशुल्क हस्तांतरित किया जाना व गृह विभाग को विधिवत कब्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ताकि गृह विभाग द्वारा इन पांचों पुलिस चैकियों के स्थापना आदेश निर्गत करते हुए इनके संचालन हेतु अपेक्षित पद सृजन आदि का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त कर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त पद सृजन किया जाएगा।

औद्योगिक विकास विभाग एवं वित्त विभाग के प्रकरण में प्राप्त परामर्श एवं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं जनहित के दृष्टिगत शेष 10 पुलिस चैकियों हेतु चिन्हित भूमि पर इन पुलिस चैकियों की स्थापना हेतु इनका निर्माण द्वितीय चरण में गृह विभाग द्वारा अपने उपलब्ध अनुदान व बजट व्यवस्था से संगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के परामर्श से सुनिश्चित कराया जाएगा।

इन पुलिस चैकियों के भूमि स्वत्व के निःशुल्क हस्तान्तरण के संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग व यूपीडा द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उससे गृह विभाग सहमत है। यदि भविष्य में सडक कभी चैड़ी होगी तो तत्समय पर यथास्थिति निर्णय लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त इन 10 पुलिस चैकियों हेतु चिन्हित भूमि, इन 10 पुलिस चैकियों की स्थापना हेतु, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित ;पूजी जपजसम वर्ा संदकद्ध निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

यूपी में सरकार ने घटाई मण्डी शुल्क

लखनऊ, 24 नवम्बर, मंत्रिपरिषद ने मण्डी परिषदों एवं अधिसूचित मण्डी स्थलों में आरोपित होने वाले मण्डी शुल्क की वर्तमान दर को 02 प्रतिशत से घटाकर 01 प्रतिशत तक एवं विकास शुल्क 0.50 प्रतिशत को यथावत रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह निर्णय किसान उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के अनुक्रम में मण्डी शुल्क की दरों में संशोधन कर कमी किए जाने के तहत लिया गया है। यह निर्णय मण्डी अधिनियम1964 की धारा 17(3)(ख) के प्राविधान के अनुसार अधिसूचना निर्गत करने के उपरान्त लागू हो जाएगा। भारत सरकार की नयी व्यवस्था के क्रम में मण्डी परिसरों के अन्दर के व्यापार को प्रासंगिक और आकर्षित बनाये रखने के लिए मण्डी शुल्क दरों में कमी किया जाना आवश्यक है। मण्डियों का व्यापार कम होने व उनका कमजोर पड़ना कृषक हित में नहीं होगा।

हवन-पजून के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर, पांडेयपुर का भव्य श्रृंगार, 151 किलों लड्डू का भक्तों ने लगाया भोग

(सुरेश गांधी)

वाराणसी। धर्म एवं आस्था की नगरी काशी के पांडेयपुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार को श्रीहनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। इस मौके पर पूरे मंदिर को तरह तरह के फूलों एवं रंग बिरंगी आकर्षक विद्युत झालारों से सजाया गया। पूरा मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजा था। सायं 6 बजे हवन के साथ बजरंगबली का विशेष हवन पूजन किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी के सदस्यों ने 151 किलों लड्डू का हनुमानजी को भोग लगाया। मंदिर में अलसुबह से ही हनुमान चालीसा व अन्य भजनों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बजरंगबली का दर्शन कर सुखशांति की प्रार्थना की।

मंदिर पुजारी के मुताबिक सुबह ब्रह्ममुहूर्त में महाआरती और विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में सुबह से ही दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर व्यापार मंडल, पांडेयपुर के अध्यक्ष एवं व्यापारी नेता मनीष गुप्ता, संतोष

जायसवाल, विनय गुप्ता, राजन गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, हृदय गुप्ता, शैलेस गुप्ता, महेश गुप्ता, सत्तन यादव, राजेश गुप्ता, दिलीप जायसवाल, कैलाश कन्नौजिया, छेदीलाल पटेल, अनिल लोकवानी, संतोष गुप्ता, रोहित विश्वकर्मा, विजय गुप्ता व अजय गुप्ता आदि का योगदान सराहनीय रहा। कभी अपने आराध्य की रक्षा तो कभी अपने भक्तों का संकट हरने, समय समय पर बजरंगबली ने कई रुप धरे है। कुछ ऐसा ही हुआ है तीनों लोकों में न्यारी, सांस्कृतिक धरोहरों की विरासत केन्द्र के साथ खूबसूरत मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी में। काशी के पांडेपुर में विराजमान है।

सरकारी केंद्रों पर धान खरीद ने बनाया रिकार्ड

सहारनपुर, 24 नवंबर (वेबवार्ता)। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इस साल सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद का नया रिकार्ड बन गया है। 2000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में अब तक 8500 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। धान की खरीद का यह सिलसिला 31 जनवरी तक चलेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रिंस चैधरी ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल 2030 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। सरकारी केंद्रों पर सामान्य प्रजाति के धान का मूल्य 1868 रूपए और अच्छी श्रेणी के धान का मूल्य 1888 रूपए प्रति क्विंटल है जबकि बाजार में धान की कीमत इस बार 400 से 500 रूपए प्रति क्विंटल तक कम है।

देवबंद के प्रमुख आढ़ती बलराम सिंघल और मोहित सिंघल ने बताया कि मंडी में सामान्य प्रजाति के धान की कीमत 1400 से 1500 रूपए प्रति क्विंटल है और बाजार में इस बार धान बहुत कम बिकने के लिए आ रहा है। बलराम सिंघल का कहना था कि बाजार में सामान्य प्रजाति के चावल की मांग कम होने से उसकी कीमत भी कम है। इसकी एक बड़ी वजह आधुनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को बहुत ही मूल्य पर चावल दिया जा रहा है। सहारनपुर जिले में धान की पैदावार का कुल क्षेत्रफल 60 हजार हेक्टेयर है।

सामान्य और मोटी प्रजाति के धान का क्षेत्रफल 12 हजार हेक्टेयर है और अच्छी किस्म के बासमती चावल का क्षेत्रफल 48 हजार हेक्टेयर है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर 16 करोड़ रूपए का धान खरीदा गया है और 14 करोड़ 25 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। यानि 90 फीसद भुगतान किया जा चुका है।

सरयू नहर के किनारे शहरों के विकास कार्य कराए जाने की कार्य योजना को स्वीकृति

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

लखनऊ, 24 नवम्बर। मंत्रिपरिषद ने सरयू नहर परियोजना फेज3 एवं अर्जुन सहायक परियोजना के अन्तर्गत प्रक्षेत्र विकास कार्य कराए जाने की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरयू नहर परियोजना फेज3 के अन्तर्गत 03 वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2020-23) में 1672.69 करोड़ रुपए व्यय कर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 08 जनपदोंगोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर में कुल 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रक्षेत्र विकास कार्य किया जाना है। इसके अन्तर्गत 25,920 कि0मी0 कच्ची गूल, 6,012 कि0मी0 पक्की गूल, 24,048 जल नियंत्रक संरचना, 48,000 हे0 क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन, 96,000 हे0 जल निकास नाली आदि का निर्माण होना है। इसके अन्तर्गत कुल 7,038 गाँवों के 6,13,937 कृषक लाभान्वित होंगे।

अर्जुन सहायक परियोजना के अन्तर्गत 03 वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2020-23) में 188.96 करोड़ रुपए व्यय कर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 02 जनपदों हमीरपुर व महोबा में कुल 0.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रक्षेत्र विकास कार्य किया जाना है। इसके अन्तर्गत 2920 कि0मी0 कच्ची गूल, 677 कि0मी0 पक्की गूल, 2710 जल नियंत्रक संरचना, 5410 हे0 क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन, 10.82 हजार हे0 जल निकास नाली आदि का निर्माण होना है। इसके अन्तर्गत कुल 216 गाँवों के 53,080 कृषक लाभान्वित होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरयू नहर परियोजना फेजIII हेतु 500 करोड़ रुपए तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। दोनों योजनाओं पर उत्पन्न व्ययभार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना है। दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना की गाइडलाइन्स तथा संगत विनियमों/नियमों/दिशानिर्देशों के अन्तर्गत किया जाना है।

कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी अदालती कार्रवाई

लखनऊ, 24 नवम्बर। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में कोरोना महामारी फैलने एवं अभी तक इसका समुचित इलाज न होने के कारण इससे बचाव हेतु लॉकडाउन, सामाजिक दूरी बनाये रखने आदि सम्बन्धी दिशा निर्देश समयसमय पर जारी किये गये हैं, जिसका प्रभाव न्यायालयों की कार्यवाही पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान न्यायालयों में समुचित रूप से सुनवाई हो पाने एवं वादी/प्रतिवादी को न्याय दिलाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई की आवश्यकता महसूस की गयी। कोविड19 के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश 24 मार्च, में सामाजिक दूरी के मानक पालन के निर्देश है। अनुच्छेद 225 व 227 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्र निर्माण में आगे आएं युवा: अनन्या सिंह

बहराइच। नवाबगंज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की इकाई नेहरू युवा केंद्र बहराईच के तत्वाधान में जिला युवा समन्वयक अनन्या सिंह के अध्यक्षता व राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक कन्हैया मिश्र के नेतृत्व में विकास खंड नवाबगंज के काशी राम अयोध्या प्रसाद इण्टर कॉलेज बाबागंज में युवा मंडल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मण्डल अध्यक्ष अजय मिश्र रहें। जिला प्रशिक्षक आदर्श मिश्र ने युवाओं को नेहरू युवा केन्द्र व युवा मंडल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की भारत विश्व का सबसे युवा देश है आज हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है फिर भी किन्ही कारणों से हम समाज को शिक्षित व जागरूक करने में असफल रह जाते है। इसके मुख्य कारण को सोचने के साथ युवाओं को आगे आकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। बिशिष्ट अतिथि विद्यालय प्रधानाध्यापक अरुण कुमार यादव ने कहा की ऐसे कार्यक्रम से सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सामने लाना तथा जोर शोर से उठाना है उन्होंने कहा कि आज देश के सामने इस बड़ी आबादी को एक उत्पाद कार्यबल के रूप में विकसित और सशक्त बनाने की जरूरत है ।

कुलपति एवं शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण प्रस्ताव अनुमोदित

(विशेष संवाददाता)

लखनऊ, 24 नवम्बर। मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोअनुसंधान संस्थान, मथुरा में कार्यरत कुलपति/शिक्षकों के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षण किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा के संवर्धन और उन्नयन के लिए उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोअनुसंधान संस्थान, मथुरा की स्थापना दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 को की गयी। छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से विश्वविद्यालय में कार्यरत कुलपति/शिक्षकों के सम्बन्ध में लागू किया गया है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना का लाभ केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं निदेशकों तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों को अनुमन्य कराए जाने के दृष्टिगत कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोअनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों (कुलपति सहित) को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में वेतन पुनरीक्षण विषयक शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया। सातवाँ केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना का लाभ उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोअनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अनुमन्य कराए जाने से उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके द्वारा पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इससे नवीन शोधों एवं नवाचारों की सम्भावना प्रबल होगी तथा पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ छात्रों, शोधार्थियों एवं जनसामान्य को प्राप्त होगा।

प्रस्तावित शासनादेश निर्गत होने से उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोअनुसंधान संस्थान, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना के लाभ का अवसर प्राप्त होगा।

शिक्षा विभाग की भारी अनियमितता पर विफ़रे ए डी बेसिक

बहराइच । पयागपुर / बिशेश्वरगंज सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा विनय मोहन वन ने बताया कि आज दिनांक 23.11.2020 को जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज व पयागपुर के विद्यालयों का निरीक्षण किया गया जो निम्नवत है। कम्पोजिट विघालय उधरना सरहदी, कम्पोजिट विघालय विशेश्वरगंज प्रथम, पी एस इन्द्रापुर, पी एस सुहेलवा, यू पी एस सुहेलवा, पी एस मुण्डेरवा ठकुराइन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि स.अ. विमर्श देवी वर्मा बिना किसी अवकाश के अनुपस्थिति रही है । अधिकांश विधालयों के अध्यापकों को मिशन प्रेरणा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है । विघालय उधरना सरहदी में किसी अध्यापकों को 3 माडूयल् की किताब नहीं मिली है । स्वेटर का वितरण शुरू हो गया है ।आन लाइन कराये जा रहे शिक्षण कार्य सन्तोष जनक नही पाया गया । शतप्रतिशत शिक्षक द्वारा दीक्षा ऐप का प्रयोग नही किया जा रहा है । बीईओ विशेश्वरगंज को कायाकल्प अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराने के साथ आनलाइन शिक्षण कार्य का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए । उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि ए डी बेसिक की सक्रियता से पुनः शिक्षा विभाग में हो रही अनियमितता फिर उजागर हुई और जिस पर विनय मोहन वन ने कड़ा रुख अख्तियार किया ।

बाल यौन शोषण पर चर्चा के लिए जुटे दुनियाभर के दिग्गज

बाल यौन शोषण और बाल तस्करी की रोकथाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। बाल यौन शोषण और बाल तस्करी की रोकथाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन भागीदारी जन सहयोग समिति की अगुवाई में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने बालदुर्व्यवहार के पीड़ितों और उनके अभिभावकों के कड़वे एवं मार्मिक अनुभवों की चर्चा को साझा किया। साथ ही बताया कि दुर्व्यवहार से उनके हृदय पटल पर इसका कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश के राज्यों क़ी विधिक सेवा प्राधिकरण बाल यौन शोषण और बाल तस्करी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका क़ी मिसाल प्रस्तुत करे।

कार्यक्रम में दिल्ली , हरियाणा , अरुणाचल प्रदेश एवं पंजाब की राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की प्रमुख भागीदारी रही तथा ओपू आमा सोसाइटी एवं अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडीज एवं पंजाब राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का सहयोग भी सम्मिलित रहा।

हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दया चौधरी न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विभिन्न कानूनी गतिविधियों पर बात की। उन्होंने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श को सिखाने के साथसाथ बाल शोषण और मानव तस्करी रोकथाम के लिए सामाजिक संस्थाओं एवं शिक्षा संस्थानों से आग्रह किया कि वे बच्चों जागरूक करे न्यायमूर्ति चौधरी के कहा कि बाल यौन शोषण के मामले रजिस्टर किये गए मामलो से कम है क्योकि जागरूकता के आभाव में पर्याप्त संख्या में दर्ज नहीं होते। हरियाणा सरकार के पूर्व पूर्व प्रधान सचिव शिव रमन गौड़ ने शहरी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पक्ष में भी योजना बनाने और कदम उठाने के लिए बच्चों, मातापिता और अन्य सामाजिक संगठनों को सतर्क और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तकनिकी सत्र की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार देबाश्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर

सेवाएं एवं पोक्सो अधिनियम जैसे कड़े कानून बनाकर देश में यौन शोषण और बाल तस्करी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इसी सत्र में ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश में लॉ विभाग की प्रोफेसर शहनाज हुडा ने बांग्लादेश में बाल यौन शोषण और बाल तस्करी के मामलों का एक सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत करते हुए इससे सम्बंधित अपने देश के कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। तथा बाल यौन शोषण के खिलाफ विश्व्यापी अभियान में सभी देशो की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।

बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति आयोग के कटिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रज्ञा परांडे ने अन्य विभागों की मदद से भारत में बच्चों के यौन शोषण और तस्करी की समस्या से निपटने के लिए आयोग द्वारा उठाए गए उपायों पर बात की।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कँवल जीत अरोरा सदस्य सचिव दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने प्राधिकरण कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा स्कूल में बच्चों एवं अध्यापकों को ही नहीं अपितु अभिभावकों को भी बाल यौन शोषण रोकथाम , कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाने के लिए एक और विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है दूसरी और पुलिस कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कानूनी प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव विजय गौड़ ने अभियान को देशव्यापी स्तर पर ले जाने की घोषणा की। साथ ही बताया कि भारत, यूएसए , इंडोनेशिया एवं बांग्लादेश से वेबिनार में 10000 लोगो ने भाग लेने के लिया रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें छात्र, प्रोफेसर, अध्यापक, समाजसेवी, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी, अधिवक्ता,एवं विभिन्न राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित 16000 से अधिक लोग कार्यक्रम से जुड़े। इसमें डीएवी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका एवं केन्दीय विद्यालयों के अध्यापको ने प्रमुखता से भाग लिया। इस अवसर पर संस्थानों के प्रमुख प्रोफेसर के के अग्रवाल, एपीएसएलएसए की सदस्य सचिव जवाप्लू चाय, प्रोफेसर आदित्य मालिक उपकुलपति के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ओपी शर्मा उपकुलपति अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडीज , सुश्री जसबीर ऋषि उपकुलपति डीएवी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ज्योति गौड़ डीन स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी ने भी बाल यौन शोषण को सामाजिक कलंक बताते हुए समिति के अभियान में सहयोग देने का विश्वास दिलाया।

नैनी (प्रयागराज) कार्यालय
नैनी स्टेशन के सामने
प्रभारी:
सुजीत चौरसिया
Mo- 9451251066

वूमेन एक्सप्रेस
स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक **सुनील पाण्डेय** ने आदित्य ग्राफिक्स **INC**, प्रताप भवन, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1 से मुद्रित व **ई–4/168**, गली नंबर–6, सागर मार्केट, साढे 4 पुस्ता, सोनिया विहार दिल्ली–94 से प्रकाशित किया।
RNI.DELHIN / 2013/ 48606
मो.– 07042999974
टेली– 09013 518 518
www.womenexpress.in
thewomenexpress@gmail.com

वूमेन एक्सप्रेस

फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा सबसे पहले कोरोना टीका

एक नजर

डिग्री कालेजों में 15 से 20 फीसद रही छात्र-छात्राओं की उपस्थिति

सहारनपुर। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिग्री कालेजों को खोलने का फैसला छात्र छात्राओं को रास नहीं आया। कोरोना के भय के बीच 15 से 20 फीसद तक छात्र कालेजों में पहुंचे। छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या ज्यादा थी। सहारनपुर के जैन डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. वकुल बंसल ने आज बताया कि कालेज में कल पहले दिन 15 फीसद छात्रछात्राएं ही कालेज पहुंचे। कक्षाओं में छात्रों को सामाजिक दूरी के साथ बैठाया गया। उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों की सफाई के बाद ही कालेज में प्रवेश दिया गया। मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कालेज की प्राचार्या डा. अमिता अग्रवाल ने कहा कि कालेज में कोविड19 के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। उनके यहां छात्राओं की उपस्थिति 60 फीसद तक रही। नगर के 2500 से अधिक छात्रछात्राओं वाले महाराज डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. अरूण कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके कालेज में पहली बार छात्रछात्राओं के लिए निर्धारित पौशाक तय की गई। कालेज में गैर छात्र भी कालेज में घुस आते थे और माहौल बिगाड़ते थे। जिले के देवबंद, नांगल, नानौता, बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगौह, नकुड़, रणखंडी, भायला और सिमलाना आदि स्थानों पर सभी डिग्री कालेजों में शिक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है।

कोरोना शादी: कार्ड बंट गये अब किसको मना करें

सहारनपुर । उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के मकसद से विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 200 के बजाए 100 कर दिए जाने से आयोजक परेशान हो गए हैं। 25 नवंबर को अकेले सहारनपुर शहर में 750 और जिले में करीब 1200 शादियां होनी हैं। इनके लिए आयोजक पूर्व के निर्देशों के तहत 200 मेहमानों को निमंत्रण कार्ड वितरित कर चुके थे। आयोजकों ने बैंडबाजों, सजावट वालों और भोजन आदि की व्यवस्था भी 200 लोगों के अनुसार की हुई है। ऐसे में आयोजकों को नए निर्देशों के अनुसार 100 अतिथियों की सीमा का पालन करना उनकी मुश्किलें बढ़ा गया है। वेंकट हाल और रिसार्ट संचालकों आदि का कहना था कि इस बार शादियों का मुहूर्त 14 दिसंबर तक ही है। ऐसे में राज्य सरकार को 15 दिसंबर तक नई गाइड लाइन नहीं लागू करनी चाहिए थी। नई गाइड लाइन के जारी होने से शादियों के आयोजक,होटल मालिक,वेंकट हाल संचालक सभी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जो कार्ड बांट चुके हैं वो कैसे मेहमानों को आने से रोके। उधर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने 14 दिनों में 15 थानों क्षेत्रों के 48 स्थानों पर कोई कोरोना संक्रमण नहीं पाए जाने से हाट स्पाट क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दी हैं।

बस्ती मे 36 हजार से अधिक श्रमिक अपने ही गांवो मे कर रहे काम

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले मे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत 36 हजार 5 सौ 25 श्रमिक अपने की गांवों मे कार्य कर रहे हैं और इनके खाते मे मजदूरी का भुगतान भेज दिया जाता है। आधिकारिक सूत्रो ने मंगलवार को यहां कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत वर्तमान मे जिले के बहादुरपुर विकास खण्ड के 75 ग्राम पंचायतो मे 154 कार्य स्थलो पर 22 सौ 11 श्रमिक, बस्ती विकास खण्ड के 92 ग्राम पंचायतो मे 190 कार्यस्थलो पर 2704 श्रमिक, गौर विकास खण्ड क्षेत्र के 96 ग्राम पंचायतो मे 152 कार्यस्थलो पर 28 सौ 28 श्रमिक, बनकटी विकास खण्ड क्षेत्र के 78 ग्राम पंचायतो मे 285 कार्यस्थलो पर 67 सौ 47 श्रमिक, रामनगर विकास खण्ड क्षेत्र के 80 ग्राम पंचायतो मे 136 कार्य स्थलो पर 17 सौ 11 श्रमिक, पंचायतो मे 187 कार्यस्थलो पर 17 सौ 89 श्रमिक, कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र के 67 ग्राम पंचायतो मे 193 कार्यस्थलो पर 45 सौ 22 श्रमिक, रूधौली विकास खण्ड क्षेत्र के 75 ग्राम पंचायतों मे 103 कार्यस्थलों पर 9 सौ 99 श्रमिक अपने ही गांवो मे कार्य कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के रोशनी घोटाला में कई दिग्गज शामिल

भाजपा ने फारूक अब्दुल्ला पर लगाए संगीन आरोप, भाजपा ने कहा-गैंग ऑफ लैंड ग्रैबर्स है गुपकार गठबंधन

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली 24 नवंबर । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जम्मूकश्मीर के रोशनी जमीन घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर 7 कनाल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि

25,000 करोड़ रुपये का रोशनी घोटाला जम्मूकश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी रोशनी एक्ट की आड़ में कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी नेताओं द्वारा सरकारी जमीन की लूट के प्रकरण की कड़ी निंदा करती है। भाजपा मांग करती है कि इस एक्ट के तहत लैंड अलॉटमेंट अविलंब रद्द किया जाए।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर की स्वायत्तता की आवाज उठाने का झूठा बहाना बनाकर कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के नेता वाले सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सुविधाएं जुटाते रहे। वास्तव में गैंग ऑफ लैंड ग्रैबर्स है गुपकार गठबंधन।

जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट का दुरूपयोग कर कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने सरकारी जमीन का बंदरबांट कर निजी फायदे के लिए अवैध तरीके से उस पर कब्जा किया। अब्दुल्ला परिवार सहित कई राजनीतिक और जाने माने लोगों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि जिसे जहां मौका लगा, उसने वहां लूट मचाई। फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया माटू और बहनोई के नाम भी कब्जे की सूची में शामिल हैं। यहां तक कि नेशनल कांफ्रेंस का दफ्तर भी रौशनी एक्ट का गलत फायदा उठाकर गैरकानूनी तरीके से बनाया

गया। जम्मू में नेशनल कांफ्रेंस का दफ्तर शेरएकश्मीर भवन को रोशनी एक्ट के तहत 3 कनाल 16 मरला सरकारी जमीन पर बना है जबकि श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस का दफ्तर भी 3 कनाल 16 मरला सरकारी जमीन कब्जा कर बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने 1998 में सजवान में 3 कनाल जमीन खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने अवैध तरीके से 7 कनाल जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। यह प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई लूट थी। इस गड़बड़ी के लिए उन्होंने रोशनी अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। बाद में उच्च न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

दरअसल, जम्मू के सजवान में फारूक अब्दुल्ला का मकान है जो 10 कनाल जमीन पर बना हुआ है। आरोप है कि इस 10 कनाल जमीन में 3 कनाल जमीन फारूक अब्दुल्ला की है जबकि बाकी 7 कनाल जमीन जंगल की है जिस पर रोशनी एक्ट का दुरूपयोग करते हुए अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं के चेहरों से नकाब उतर गया है। हाई कोर्ट के आदेश में उन नेताओं की पहली सूची सार्वजनिक हुई है जिन्होंने सरकार की संपत्ति को अपनी और परिवार की संपत्ति में बदल दिया था। जांच में पीडीपी सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉ हसीब द्राबू समेत कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के कई पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों, व्यापारियों और इनके रिश्तेदार भी शामिल हैं।

इन्होंने गरीबों के घर रोशन करने के नाम पर बनाए गए कानून की आड़ लेकर करोड़ों की सरकारी जमीन हड़प ली। बताया जाता है कि हजारों करोड़ के इस घोटाले में शामिल लोगों की अभी तीन से चार और सूची आएंगी। इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।

क्या है पूरा मामला

जम्मूकश्मीर राज्य भूमि अधिनियम, 2001 तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार गरीब तबके के लोगों को विधिपूर्वक जमीन उपलब्ध कराने और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से लेकर आई थी। इस कानून को रोशनी नाम दिया गया। इस कानून के अनुसार, भूमि का मालिकाना हक उसके अनधिकृत कब्जेदारों को इस शर्त पर दिया जाना था कि वे लोग मार्केट रेट पर सरकार को भूमि का भुगतान करेंगे। इसकी कट ऑफ 1990 में तय की गई थी। शुरुआत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को कृषि के लिए मालिकाना हक दिया गया। हालांकि इस अधिनियम में दो बार संशोधन किए गए जो मुफ्ती सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार के कार्यकाल में हुए। उस दौरान इस कानून की कट ऑफ पहले 2004 और बाद में 2007 कर दी गई।

भारत में कोविड के 37,975 नए मामले कुल मामले बढ़कर 91.77 लाख

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 24 नवंबर । देश में एक दिन में कोविड19 के 37,975 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91.77 लाख के पार चले गए, जिनमें से 86 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे अद्यतन किये गये आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल 91,77,840 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 480 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,34,218 हो गई। इन 480 लोगों में से 121 लोग राष्ट्रीय राजधानी के हैं। इसमें कहा गया है कि देश में लगातार 14 दिन से उपचाराधीन मामलों की संख्या पांच लाख से कम है। अभी कुल 4,38,667 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कुल

मामलों का 4.78 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 86,04,955 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही, मरीजों के ठीक होने की दर 93.76 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड 19 से मृत्यु दर 1.46 प्रतिशत है। भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं, कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 23 नवम्बर तक कुल 13.36 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड19 संबंधी जांच की गई, जिनमें से 10,99,545 नमूनों का परीक्षण सोमवार को ही किया गया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में से जिन 480 लोगों की मौत हुई।

भाकियू की मांग 450 रूपए प्रति क्विंटन हो गन्ने की कीमत

सहारनपुर । भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) अध्यक्ष चैधरी नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस बार गन्ना मूल्य कम से कम 450 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाये। जिले के रामपुर मनिहारान तहसील के उमाही कलां गांव में किसानों की सभा को संबोधित करने के बाद टिकैत ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रूपए प्रति क्विंटल है। पिछले तीन पेराई सत्रों के दौरान उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं की है जबकि गन्ने की लागत में इस दौरान काफी वृद्धि हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों का करोड़ों रूपया चीनी मिलों की ओर बकाया है। प्रदेश के चीनी मिल नियमानुसार 14 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करते हैं और न ही बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज का भुगतान करते हैं।

ग्रामीण, कृषि अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भरता के लिए: गडकरी

(विशेष संवाददाता)

पुणे, 24 नवंबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि की गिनती आत्मनिर्भरता की दृष्टि से '' महत्वपूर्ण क्षेत्रों'' में करते हुए मंगलवार को कहा कि ''आत्मनिर्भर भारत'' की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सोच देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएगी। 'आत्मानिर्भर भारत' पर सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला में गडकरी ने कहा, ''हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत' को लागू करने के लिए नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है। गडकरी ने कहा कि यह केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भी हर क्षेत्र के लिए एक दृष्टि पथ बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि दो ऐसे क्षेत्र हैं जो 'आत्मानिर्भरता' के लिए

महत्वपूर्ण हैं और हमें इन पहलुओं पर एक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि 'आत्मनिर्भरता' का मुख्य स्तंभ है क्योंकि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि समृद्ध होगी तो ग्रामीण भारत भी समृद्ध होगा।'' मंत्री ने कहा कि छोटे स्थानों, गांवों, किसानों और अन्य लोगों को मजबूत करने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आयात को कम करने और निर्यात का संवर्द्धन करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। गडकरी ने कहा, ''हमें उन विकल्पों का पता लगाने की जरूरत है, जो आयात का विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम कच्चे तेल का आयात करते हैं, लेकिन हमारे किसान गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन करके एक विकल्प प्रदान कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कई विकल्पों का फायदा उठाया जा सकता है।

हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना को मंजूरी

लखनऊ, 24 नवम्बर। मंत्रिपरिषद ने जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजनान्तर्गत द्वितीय चरण (वर्ष 2020-21 से 2022-23) के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर से 'जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की योजना' के 03 वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम चरण का कार्य वित्तीय वर्ष 201617, 201718 एवं 2018 19 में संचालित किया गया। योजना के द्वितीय चरण का 03 वर्षीय कार्यक्रम वर्ष 202021 से 2022 23 तक पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर 14.28 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। योजना से किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादित जैविक कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था में रोजगार सृजन भी बढ़ेगा तथा कृषि की लागत में कमी आएगी। द्वितीय चरण (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक) में जनपद हमीरपुर के सभी सात विकास खण्डों में 20 क्लस्टर प्रति विकास खण्ड कुल 140 क्लस्टर में जैविक खेती के विकास की योजना तथा समस्त 07 विकास खण्डों में 700 हे0 प्रति विकास खण्ड, इस प्रकार कुल सभी 07 विकास खण्डों में 4,900 हे0 क्षेत्रफल में जीरो बजट प्राकृतिक खेती की योजना प्रस्तावित है। जैविक खेती कृषि की यह पद्धति है, जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पद्धति रसायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती स्वावलम्बी एवं स्थायी है। जैविक खेती से लक्षित उत्पादन प्राप्त करते हुए प्रकृति की सम्पदा, मृदा जीवांश, जल, वायुमण्डल के जीवों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है तथा मानव स्वास्थ्य पर रसायनों से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

बिजलीकर्मी को महिला इंस्पेक्टर ने मारा थप्पड़, साथियों ने काट दी 35 गांव की बिजली

(विशेष संवाददाता)

बदायूं । उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक महिला इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। महिला इंस्पेक्टर के थप्पड़ मारने का खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा। दरअसल शहर में चेकिंग के दौरान मास्क न पहनने पर महिला इंस्पेक्टर का विद्युतकर्मी से विवाद हो गया था। वर्दी के रौब में आई महिला इंस्पेक्टर ने विद्युत कर्मी को थप्पड़ जड़कर सरकारी जीप से थाने ले आईं। इस कार्रवाई पर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अन्य स्टाफ भड़क उठा और हंगामा कर दिया। स्टाफ उपकेंद्र पर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं गुस्साए कर्मचारियों ने 35 गांवों की बिजली काट दी। बाद में पुलिस ने ऑपरेटर को रिहा किया तो मामला शांत हुआ। कुंवरगांव विद्युत उपकेंद्र पर ऑपरेटर के रूप में तैनात सुनील कुमार अपने गांव गरुईया से ड्यूटी के लिए उपकेंद्र पर आए थे। ड्यूटी के दौरान उनके पेट में दर्द उठा तो वह अपनी बाइक से चौराहे पर दवा लेने निकल पड़े, मगर जल्दबाजी में अपना

मास्क पहनना भूल गए। इधर, चौराहे पर चेकिंग कर रही महिला इंस्पेक्टर ने सुनील कुमार की बाइक रोकी। मास्क न पहनने पर इंस्पेक्टर ने सुनील कुमार पर जुर्माना लगा दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच तल्खी बढ़ी तो इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर सुनील कुमार को थप्पड़ मार दिया और उनको सरकारी जीप में बैठाकर थाने ले आई। अपने सहयोगी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अन्य स्टाफ भड़क गया और थाने आकर हंगामा करने लगे। इसके बाद स्टाफ उपकेंद्र पर ही धरने पर बैठ गया। गुस्साए विद्युत कर्मियों ने नगर समेत इलाके के करीब 35 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी और नारेबाजी करने लगे। अंत में इंस्पेक्टर ने सुनील कुमार को रिहा कर दिया। महिला इंस्पेक्टर शर्मिला शर्मा को हाल में कुंवरगांव थाने पर तैनाती मिली है और वह पदोन्नत होकर इंस्पेक्टर बनी हैं। उधर, इंस्पेक्टर शर्मिला शर्मा ने कहा कि विद्युतकर्मी से मास्क न पहनने का कारण पूछा था। इस बात पर वह अभद्र व्यवहार करने लगा। इसीलिए कार्रवाई करनी पड़ी। इस बावत सीओ सिटी विनय द्विवेदी के मुताबिक महिला इंस्पेक्टर से बिजलीकर्मी का मास्क को लेकर विवाद हुआ था।

दिल्ली की दमघोंटू हवा, एयर क्वॉलिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में

नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर के 38 में से 18 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सरकारी एजेंसियों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मोबाइल ऐप समीर के अनुसार मंगलवार की शाम शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 388 दर्ज किया गया जबकि सुबह में यह 361 था। आनंद विहार (413), बवाना (412) अशोक विहार (407), चांदनी चौक (410), जहांगीरपुरी (424), पटपड़गंज (411) और विवेक विहार (426) केंद्रों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली का एक्यूआई सोमवार को 302, रविवार को 274, शनिवार को 251, शुक्रवार को 296, बृहस्पतिवार को 283 और बुधवार को 211 दर्ज किया गया था। दरअसल शून्य से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'अत्यंत खराब' और 401 से 500 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता

है। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है ।

शुरू हुआ 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, 115 फिल्में प्रदर्शित होंगी

महोत्सव में विभिन्न भाषाओं की कुल 372 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली 24 नवम्बर । विज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण की वर्चुअल रूप से शुरुआत हो चुकी है। यह फिल्म महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार एवं त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को वर्चुअल रूप से किया है। यह चार दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव 24 से 27 नवंबर 2020 तक चलेगा। इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान को फिल्मों के माध्मय से आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए किए जा रहे विज्ञान प्रसार के प्रयास प्रशंसनीय है। पूर्वोत्तर भारत और विशेष रूप से त्रिपुरा, जो सांस्कृतिक एवं जैव विविधता के साथसाथ विशिष्ट जीवन शैली के लिए जाना जाता है, में फिल्मों के माध्यम से विज्ञान को आम लोगों तक ले जाने की पहल सराहनीय है। यह पहल इस क्षेत्र के लोगों में वैज्ञानिक चेतना के विकास में मददगार होगी।

त्रिपुरा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव तनुश्री देव वर्मा ने कहा कि कोविड19 के कारण उभरी समस्याओं के साथसाथ हमें यह अवसर भी मिला है कि हम इस ऑनलाइन आयोजन के जरिये व्यापक जनसमुदाय तक पहुँच सकते हैं, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिल सकता है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जैव विविधता एवं

जीवन शैली के कारण त्रिपुरा समेत संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत युवाओं एवं सांस्कृतिक समुदाय के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के उद्देश्य से बनायी जाने वाली फिल्मों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र हो सकता है।

विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ नकुल पाराशर ने कहा कि अपनी तीन दशक की यात्रा में विज्ञान प्रसार ने निरंतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। विज्ञान फिल्म महोत्सव इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। इस वर्ष लॉकडाउन से पहले मार्च में अगरतला में यह आयोजन होना था, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। लेकिन, महामारी के प्रकोप को देखते हुए विज्ञान फिल्म फेस्टिवल को स्थगित करना पड़ा और अब यह वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया की नज़रें वैक्सीन के विकास पर टिकी हुई हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आगामी राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव अपने वास्तविक स्वरूप में आयोजित हो सकेगा।

इस वार्षिक फिल्म महोत्सव में इस साल विभिन्न भाषाओं की कुल 372 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। दस सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा इनमें से चुनी गई 115 फिल्मों को इस ऑनलाइन विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और तमिल भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में विभिन्न पेशेवरों, अलगअलग संस्थानों, निर्माताओं, छात्रों एवं अलगअलग आयु वर्ग के लोगों द्वारा बनायी गई हैं। इस महोत्सव में डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, एनिमेशन एवं साइंस फिक्शन वर्गों में फिल्में आमंत्रित की गई थीं। ये फिल्में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं औषधि, बायोग्राफी, कृषि, परंपरागत ज्ञान और विज्ञान के इतिहास जैसे विषयों पर केंद्रित हैं।

इस फिल्म महोत्सव में सरकारी अनुदान पर आधारित फिल्मों के साथ साथ स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, मीडिया अध्ययन संस्थानों, कॉलेज छात्रों एवं विश्वविद्यालयों और स्कूली छात्रों की फिल्मों के लिए मुख्य रूप से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा इस वर्चुअल महोत्सव में विज्ञान, मीडिया, स्वास्थ्य और सिनेमैटोग्राफी जैसे विषयों पर चर्चाएं भी आयोजित होंगी। आयोजन के आखिरी दिन पुरस्कृत होने वालीउत्कृष्ट विज्ञानफिल्मों के नामों की घोषणा की जाएगी।

विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के प्रमुख निमिष कपूर ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि ÷विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि और पारंपरिक ज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाली फिल्मों के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जाता है।